● वर्ष-2
● अंक-263
रायपुर, रविवार 25 जून 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

अवकाश सूचना

समाचार पचीसा के कार्यलय में 25 जून रविवार अवकाश रहेगा। समाचार पचीसा का अगला अंक 27 जून मंगलवार को प्रकाशित होगा।

भारत के और करीब आ रहा मिस्र

प्रधानमंत्री मोदी दो दिवसीय यात्रा पर मिस्र पहुंचे, जोरदार स्वागत

काहिरा। पीएम मोदी अमेरिका के दौरे के बाद अब मिस्र की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। मिस्र एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी ने अपने देश में मेगा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश और भागीदारी के लिए भारत से संपर्क किया। ये ऐसे वक्त में सामने आयाजब चीन के मिस्र के साथ आर्थिक संबंध पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रहे थे। चीन के लिए ये झटका दोनों पक्षों द्वारा बीते महीने जारी संयुक्त बयान में भी परिलक्षित हुआ, जिसमें कहा गया कि दोनों नेताओं ने मिस्र में भारतीय निवेश के विस्तार का स्वागत किया। वर्तमान में . 3.15 बिलियन से अधिक है। इसमें कहा गया है कि वे एक-दूसरे के देशों में उभरते आर्थिक और निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए अपने-अपने देशों के व्यवसायों को प्रोत्साहित करने पर सहमत हुए।

स्वेज नहर क्षेत्र का विकास, जिसमें कई प्रमुख औद्योगिक और रसद क्षेत्र शामिल हैं, रेखांकित प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। मिस्र पक्ष स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र (एससीईजेड) में भारतीय उद्योगों के लिए भूमि का एक विशेष क्षेत्र आवंटित करने की संभावना पर विचार कर रहा, जिसके लिए भारत की तरफ से मास्टर प्लान पेश किया जा सकता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत आए सिसी ने जनवरी में दिल्ली में एक बैठक के दौरान व्यापारिक समुदाय से कहा कि भारतीय कंपनियां उत्पादन और विभिन्न

देशों में पुन: निर्यात के केंद्र के रूप में मिस्र की रणनीतिक स्थिति का लाभ उठा सकती हैं, जो उनके देश के मुक्त व्यापार समझौतों से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में, 50 से अधिक भारतीय कंपनियों का मिस्र में 3.15 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश है। इसके विपरीत, भारत में मिस्र का निवेश केवल 37 मिलियन डॉलर है। मिस्र के साथ भारत का व्यापार 2018-19 में 4.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 7.26 बिलियन डॉलर हो गया है।

सिसी चीनी निवेश को भी आकर्षित कर रहे हैं और पिछले आठ वर्षों में सात बार चीन का दौरा कर चुके हैं, जिसमें बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक भी शामिल है। चीन और मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार फिलहाल 15 अरब डॉलर का है। हालाँकि, मिस्र मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी से जूझ रहा है, जो पांच साल के उच्चतम 21 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जिससे अंडे, दूध और बुनियादी भोजन सहित वस्तुओं और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें आसामन पर हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय मुद्रा ने एक वर्ष से भी कम समय में अपना लगभग आधा मूल्य खो दिया है, जो डॉलर के मुकाबले 30 मिस्र पाउंड के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। देश ने छह साल में चौथी बार बेलआउट के लिए आईएमएफ से संपर्क किया है, चार साल में 3 अरब डॉलर प्राप्त किए। भारत के लिए, मिस्र के साथ मजबूत संबंध महत्वपूर्ण हैं, जिसका एक महत्वपूर्ण भू-रणनीतिक स्थान है। स्वेज़ नहर वैश्विक व्यापार के 12 प्रतिशत को नियंत्रित करती है और मिस्र पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में एक प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ी है। यह पश्चिम एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है, जो इसे एक प्रमुख बाजार और यूरोप और अफ्रीका का प्रवेश द्वार बनाता है। मिस्र के प्रमुख अरब देशों और अफ्रीकी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते भी हैं।

प्रधानमंत्री के दौरे से खौफ में इस्लामाबाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे को लेकर पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। पाकिस्तान को अंदेशा इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काहिरा यात्रा के बाद भारत और मिस्र के जुगलबंदी से इस्लामी सहयोग संगठन (आईओसी) में न सिर्फ सेंधमारी होगी बल्कि पाकिस्तान की आतंकवाद फैलाने वाली साजिशों का पर्दाफाश होगा। जानकारों का कहना है कि यही वजह है पाकिस्तान ने एक बार फिर से मिस्र को इस्लामी सहयोग संगठन से बाहर करने की साजिश रचनी शुरू कर दी हैं। वहीं, विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद लड़खड़ाई हुई अर्थव्यवस्था वाले मिस्र को अपने देश के विकास और वित्तीय मदद की उम्मीदें जगी हैं। विदेशी मामलों के जानकार कर्नल एसएन पुरी कहते हैं कि भारत और विश्व की ऐतिहासिक यात्रा को लेकर पाकिस्तान की निगाहें सबसे ज्यादा लगी हुई है। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्र मुस्लिम देशों के संगठन में शामिल होने के बाद भारत का हमेशा से सहयोग करता आया है। इसके अलावा मिस्र की चार दशक से इजरायल के साथ बड़ी रणनीति भागीदारी और रिश्ते भी हैं। भारत और इजरायल के मजबूत रिश्ते समूची दुनिया में किसी से छिपे नहीं है।

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मांग

नई दिल्ली। हिंसा प्रभावित मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। 3 मई को मणिपुर में जातीय झड़पें शुरू होने के बाद से लगभग 120 लोगों की मौत हो गई है और 3,000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। यह बैठक करीब 3 घंटे तक चली। सर्वदलीय बैठक के लिए जारी एक बयान में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल ने केंद्र पर मणिपुर के लोगों की जरूरतों की 'अनदेखी' करने का आरोप लगाया। वहीं राजद के नेता मनोज झा ने कहा कि हमने अपनी चिंताएं सरकार के सामने रखी हैं।

मणिपुर को कश्मीर बनाने की कोशिश हो रही!

बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने प्रश्न किया कि क्या सरकार 'मणिपुर को कश्मीर में बदलने की कोशिश कर रही है।' इस बैठक में तृणमूल का प्रतिनिधित्व राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर बहुत विकट स्थिति में है तथा केंद्र सरकार बुरी तरह विफल हुई है। मणिपुर पर हुई सर्वदलिय बैठक के बाद राजद के सांसद मनोज झा ने कहा कि खुले मन से बात हुई हम सबने अपनी राय रखी। वहां की राजनीतिक नेतृत्व में (लोगों का) अविश्वास है और यह बात सारे विपक्षी दलों ने रखी। हमने कहा कि जो इंसान प्रशासन चला रहा है उसमें कोई विश्वास नहीं है। अगर आपको शांति बहाल करनी है तो आप ऐसे व्यक्ति के रहते नहीं कर सकते।

समाजवादी पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मांग की। वहीं शिवसेना (यूबीटी) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पीएम मोदी को मणिपुर हिंसा को देखना चाहिए।

दुखद है मणिपुर पर पीएम ने एक शब्द नहीं कहा- डीएमके

वहीं डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने कहा कि हमने मणिपुर को लेकर अपनी चिंताएं रखी हैं। 100 लोग मारे गए हैं और करीब 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं। इस पर सबसे दुखद यह है कि प्रधानमंत्री ने इस पर एक शब्द तक नहीं कहा। वहां की स्थिति का अच्छे से पता लगाने के लिए एक सर्वदलीय दल को मणिपुर भेजना चाहिए। गृह मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है।

कांग्रेस बोली- चुप्पी तोड़ें पीएम मणिपुर की पीड़ा देश की पीड़ा

सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहे मणिपुर के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता ओकराम इबोबी सिंह ने कहा कि जब मैंने अपने सुझाव देना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि वह सुनना नहीं चाहते थे। मैंने यह भी कहा कि इसे मुद्दे पर राजनीति करने का समय नहीं है क्योंकि राज्य में सामान्य स्थिति लाने की जरूरत है। मणिपुर पर हुई सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 2001 में जून के महीने में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब मणिपुर जल रहा था। उसके बाद मणिपुर अमन, शांति और विकास के रास्ते पर लौट आया उसका प्रमुख कारण था इबोबी सिंह(मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री) ने 15 साल वहां स्थिर सरकार दी।

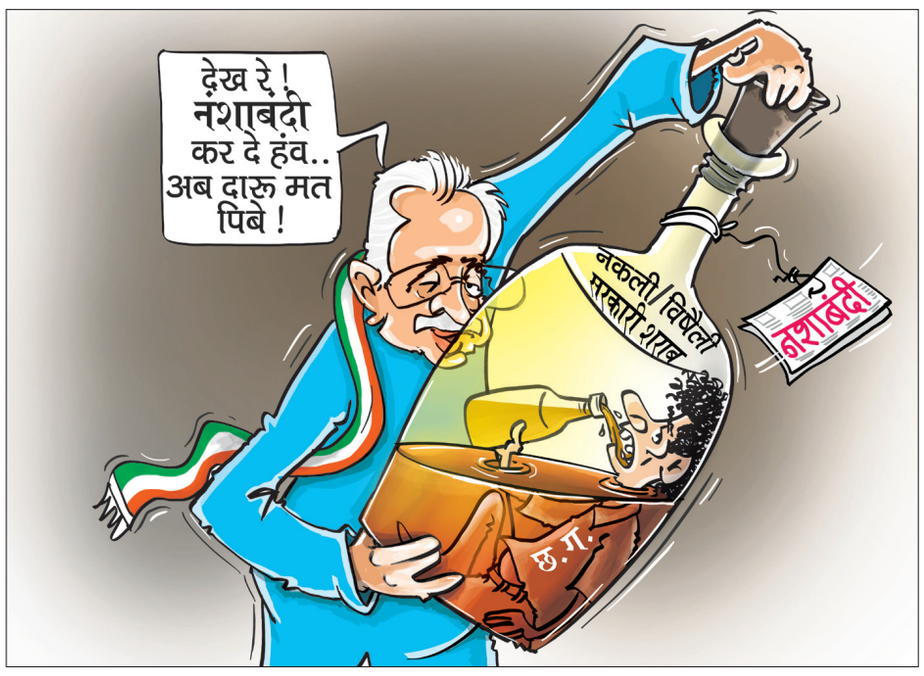

शून्य पर आउट होने वाली आरजेडी भाजपा को चुनौती दे रही: सुशील

पटना। पटना में शुक्रवार को हुए विपक्षी दलों की बैठक को लेकर राजनीति जबरदस्त तरीके से जारी है। भाजपा विपक्षी दलों की बैठक पर लगातार निशाना साध रही है। बिहार की राजनीति भी गर्म हो गई है। राजद और भाजपा के बीच जुबानी जंग भी जारी है। इन सब के बीच बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने राजद पर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि लोकसभा चुनाव में शून्य पर आउट होने वाली राजद भाजपा को चुनौती दे रही है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन बनने के बाद राज्य में 3 उपचुनाव हुए। गोपालगंज और कुढ़नी में भाजपा की जीत हुई और मोकामा में पहली बार भाजपा चुनाव लड़ी और 64 हजार वोट लाई। मोदी ने कहा कि महागठबंधन धीरे-धीरे बिहार में टूट रहा है। पहले उपेंद्र कुशवाहा फिर आरसीपी सिंह और अब जीतन राम मांझी अलग हो गए। पिछले 10 माह में महागठबंधन में न तो कोई बड़ा नेता और न ही कोई अन्य दल जुड़ा।

11 दलों के कुल सांसदों की संख्या 24

मोदी ने कहा कि विपक्ष की बैठक में जो 15 दल शामिल हुए उसमें राजद, पीडीपी और माले तीन दल ऐसे थे जिनका लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, आप के मात्र 1-1 सांसद और सीपीआई के दो तथा सीपीएम के मात्र तीन सांसद हैं। बैठक में शामिल 11 दलों के कुल सांसदों की संख्या 24 है। ऐसे दल 303 संख्या वाले भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2019 में मायावती समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल मिलकर चुनाव लड़े फिर भी भाजपा को 64 सीटें आई थी। मोदी ने कहा कि 'दिल मिले न मिले परंतु हाथ जरूर मिलाएंगे' वाले गठबंधन को कभी जनता स्वीकार नहीं करेगी।

हमने फासीवादी ताकतों को हराने का संकल्प लिया: तेजस्वी

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से पटना में बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के नेताओं ने फासीवादी ताकतों को हराने का संकल्प किया। पिता लालू प्रसाद यादव के साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में शामिल होने वाले तेजस्वी ने कहा, बैठक में कोई समस्या नहीं हुई। हर मुद्दे पर सौहार्दपूर्ण तरीके से चर्चा हुई। उन्होंने कटाक्ष किया, फोटो सेशन क्या होता है, इसके बारे में वे बेहतर जानते होंगे। तेजस्वी ने कहा, बैठक में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के नेता फासीवादी ताकतों को हराने के एकमात्र लक्ष्य से साथ आए।

प्रमुख समाचार

धर्म परिवर्तन का अनोखा आरोप, दिए जांच के आदेश

लखनऊ। चिकित्सीय लापरवाही के एक कथित मामले में बरेली के एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने कथित तौर पर एक बच्चे का खतना कर दिया, जिसे बोलने में कठिनाई होने के कारण जीभ के ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था। संज्ञान लेते हुए, स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को आरोपों की जांच शुरू की और अस्पताल से उपचार विवरण की मांग की। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी बरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है। पाठक ने कहा कि जांच 24 घंटे के भीतर पूरी होनी चाहिए। अगर आरोप सही हैं, तो अस्पताल को तुरंत सील कर दिया जाएगा। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने वाले माता-पिता के अनुसार, ढाई साल का बच्चा बोलने में समस्या का सामना कर रहा था और उसे जीभ टाई के लिए ऑपरेशन की सलाह दी गई थी। हमारी मांग है कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस बीच, डॉक्टरों ने पुलिस को बताया है कि बच्चे को मूत्र संबंधी समस्या थी।

सीपीएम भ्रष्टाचार में लिप्त, खुश करने में लगी है: वेणुगोपाल

नई दिल्ली। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के प्रमुख के सुधाकरन को शुक्रवार को पुलिस की अपराध शाखा शाखा ने धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस केरल सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हो गई है। गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद, के सुधाकरन ने शनिवार को जरूरत पड़ने पर केपीसीसी

प्रमुख का पद छोड़ने की पेशकश की, हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने इस सुझाव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह इस मामले को लड़ने के लिए उन्हें सभी राजनीतिक और कानूनी समर्थन देगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ढ्ढष्ट एवं ढ्ढष्ट के. सुधाकरन के साथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि ष्टक्क पूरी तरह से केरल में भ्रष्टाचार में लिप्त है, वे करेल में आपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं।

मिशन तेलंगाना, 25 जून जेपी नड्डा का दौरा

नई दिल्ली। तेलंगाना में अपने जनाधार मजबूत करने में भाजपा लगातार जुटी हुई है। इसी कड़ी में जेपी नड्डा 25 जून को तेलंगाना का दौरा करेंगे। इस दौरान तेलंगाना में जेपी नड्डा कि कई कार्यक्रम हो सकते हैं। तेलंगाना में इस विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में जेपी नड्डा का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तेलंगाना में भाजपा के चंद्रशेखर राव की सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर रहती है। उनकी सरकार पर भाजपा भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाती है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए रविवार को तेलंगाना के नगरकुर्नूल में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। हैदराबाद से लगभग 140 किलोमीटर दूर नगरकुर्नूल में सार्वजनिक बैठक के अलावा, भाजपा के आउटरीच अभ्यास के हिस्से के रूप में नड्डा के हैदराबाद में कुछ सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों से मिलने की संभावना है।

अजित पवार बोले- बीआरएस को हल्के में न लें

तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव या केसीआर के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में पैठ बनाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर रही है। बीआरएस ने हाल के महीनों में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में रैलियां आयोजित की हैं, जिनमें भीड़ भी उमड़ी। सीएम केसीआर अपने पूरे मंत्रिपरिषद के साथ 26 जून को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंढरपुर मंदिर शहर में पहुंच रहे हैं। वे सभी आषाढ़ी एकादशी से दो दिन पहले 27 जून को पंढरपुर में प्रसिद्ध श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर का दौरा करेंगे। बीआरएस के महाराष्ट्र किसान सेल के प्रमुख माणिक कदम ने कहा कि केसीआर ने पिछले दिनों पंढरपुर मंदिर का दौरा किया था। इस बार उनके नेतृत्व में पूरा तेलंगाना मंत्रिमंडल पंढरपुर में होगा। बीआरएस ने शहर में केसीआर कैबिनेट की उपस्थिति के दौरान पंढरपुर में एक हेलीकॉप्टर से वारकरियों पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाने की भी योजना बनाई है।

अब नए और अपग्रेड किए हुए ई-पासपोर्ट मिलेंगे: जयशंकर

नईदिल्ली। पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत जल्द ही पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी-संस्करण 2.0) के दूसरे चरण को शुरू करेगा, जिसमें नए और उन्नत ई-पासपोर्ट शामिल हैं। जयशंकर ने भारत और विदेश में पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों से लोगों को समय पर विश्वसनीय, सुलभ, पारदर्शी और कुशल तरीके से पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान करने की प्रतिज्ञा को अपग्रेड करने में शामिल होने का आह्वान किया। जयशंकर ने पासपोर्ट सेवा केंद्र पर अपने संदेश में कहा कि हम जल्द ही नए और उन्नत ई-पासपोर्ट सहित पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम संस्करण 2.0 शुरू करेंगे। नागरिकों के लिए जीवन जीने में आसानी को बढ़ाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, ये पहल ईज़ यानी ई से डिजिटल इको-सिस्टम , ए- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित सेवा वितरण एस- चिप-सक्षम ई-पासपोर्ट, ई- बढ़ी हुई डेटा सुरक्षा का उपयोग करके नागरिकों के लिए उन्नत पासपोर्ट सेवाएं के एक नए प्रतिमान की शुरुआत करेंगी।

विपक्ष की बैठक

ममता का फार्मूला माना तो देश के आधे राज्यों से बाहर होगी कांग्रेस

राहुल संपाल

बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को विपक्षी दलों की अहम बैठक हुई। इसमें विरोधी दलों के नेता मल्लिकार्जुन खरगे से लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार और अखिलेश यादव समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य एजेंडा 2024 के आम चुनाव में एकजुट होकर भाजपा को हराना है। इस बैठक से पहले सुगबुगाहट है कि विपक्ष 450 सीटों पर साझा उम्मीदवार उताकर भाजपा को चुनौती देगी। हालांकि इसमें सबसे बड़ा पेंच यह है कि सीटों का बंटवारा कैसे किया जाएगा। कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या कांग्रेस पार्टी कम सीटों पर समझौता करेगी।

कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस की जीत के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक प्रस्ताव दिया था। ममता ने आगामी लोकसभा चुनाव की मद्देनजर रखते हुए साफ कहा था कि, हम उन राज्यों में कांग्रेस का समर्थन करेंगे जहां पर उसकी जड़ें मजबूत हैं। इसके बदले में कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को उनके गढ़ में समर्थन देना चाहिए। इसके अलावा ममता ने पारस्परिक गठबंधन की शर्त भी रखी।

ममता ने यह तक कहा था कि, ऐसा नहीं हो कि किसी राज्य में हम कांग्रेस को समर्थन करे और दूसरे राज्य में कांग्रेस हमारे खिलाफ लड़ाई लड़े। अगर कांग्रेस कुछ अच्छा हासिल करना चाहती हैं तो उसे कुछ क्षेत्रों में त्याग करना पड़ेगा। ममता ने अन्य राज्यों और पार्टियों के को लेकर भी प्रपोजल दिया है। ममता पश्चिम बंगाल में भाजपा को कमजोर

करने के लिए बिना शर्त समर्थन हासिल करना चाहती हैं। साथ ही वह कहती हैं कि सपा में अखिलेश यादव की सपा मजबूत है। इसलिए हमें यूपी में सपा का समर्थन करना चाहिए।

ममता समेत अन्य क्षेत्राीय दलों का का प्रपोजल उन सीटों से है जिन पर 2019 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और जिन पर वह भाजपा के मुकाबले दूसरे नंबर पर थी। आज कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात सहित देश भर की लगभग 200 लोकसभा सीटों पर मजबूत है। इन 200 लोकसभा सीटों में से 91 सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में हैं। अगर विपक्षी एकता दल ममता के इस फार्मूले पर राजी होते है तो कांग्रेस को 230 सीटों से जयादा सीटे मिलना मुश्किल है। वह भी ये सीटें हैं, जिन पर 2019 में कांग्रेस ने या तो जीत दर्ज की थी या वो भाजपा के मुकाबले दूसरे नंबर पर रही। जबकि 34 सीटें ऐसी हैं जहां पर क्षेत्रीय पार्टियों के मुकाबले कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही।

इस रणनीति पर काम कर रही कांग्रेस

वरिष्ठ पत्रकार संजीव आचार्य कहते है कि, अभी सोचने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी इस विपक्षी एकता के मंच को लेकर कितनी गंभीर है। क्योंकि वह कभी तो कांग्रेस पार्टी के लिए प्यार दिखाती है तो कभी उनका रवैया बिल्कुल बदल जाता है। ममता अगर अपना रुख साफ करे तो कांग्रेस भी हाथ आगे बढ़ाने से नहीं हिचकिचाएंगी। हालांकि कांग्रेस भी इस दुविधा में है कि अगर ममता के फार्मूले को वह मनाती है तो फिर पार्टी का पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में उसका सफाया हो जाएगा।वरिष्ठ पत्रकार आचार्य का कहना है कि, ममता बनर्जी इस तरह की शर्ते बहुत ही सोच समझकर रखती है। वे हमेशा से अपनी पार्टी के लिए दोनों तरफ के रास्ते खुले रखना चाहती है। आज अगर भाजपा विरोधी दलों को एक मंच पर आना है तो उन्हें सबसे पहले शर्तें छोड़नी पड़ेगी। कांग्रेस के लिए आज की स्थिति अपने अस्तित्व बचाने की है। क्योंकि कांग्रेस भी यह जानती है कि 2024 में कोई खास परिवर्तन नहीं हो जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी प्रदेशों में अपनी स्थिति मजबूत करने और सत्ता हासिल करने की रणनीति पर काम कर रही है। क्योंकि कांग्रेस भी यह जानती है कि, प्रदेशों में उसे सबसे ज्यादा नुकसान क्षेत्रीय दलों ने पहुंचाया है। जो पहले कांग्रेस का वोट बैंक था वह आज क्षेत्रीय दलों में शिफ्ट हो गया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें देना पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।वरिष्ठ पत्रकार संजीव आचार्य बताते है कि, पश्चिम बंगाल में 42 सीटे हैं। पिछला चुनाव कांग्रेस और वाम दल मिलकर लड़े थे। लेकिन दो ही सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी। अगर ममता का फार्मूला यह लागू करे तो कांग्रेस को केवल दो ही सीट मिलेगी। इसी तरह यूपी में 80 सीटे है।

पोटियाडीह कांग्रेस इकाई की बैठक में बूथ कमेटी का चयन

■ बूथ कांग्रेस कमेटी संगठन की नींव - विजय देवांगन

धमतरी। विधानसभा धमतरी में चलाये जा रहे बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत आमदी जोन अंतर्गत ग्राम पोटियाडीह में जोन प्रभारी महापौर विजय देवांगन, जोन सहप्रभारी परमानंद आडिल, जोन अध्यक्ष मनोज साहू, सेक्टर अध्यक्ष आमदी गजेंद्र कुम्भकार, सेक्टर अध्यक्ष पोटियाडीह रितु साहू, फक्कीर चंद वर्मा के उपस्थिति में बूथ कांग्रेस कमेटी गठन हेतु कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के द्वारा लगातार बूथ स्तर पर पहुंचकर बूथ कांग्रेस कमेटी की मजबूती के लिए कार्य किया जा रहा है। आमदी जोन के प्रभारी महापौर देवांगन लगातार क्षेत्र के विभिन्न गांव में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बूथ गठन की प्रक्रिया को संचालित कर रहे हैं।

बैठक में बूथ कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों के चयन के साथ-साथ अन्य संगठनात्मक विषयो पर विचार विमर्श किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महापौर विजय देवांगन ने बूथ कांग्रेस कमेटी को संगठन की नींव बताया। आगे कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एक लोकतांत्रिक संगठन है जहां बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव कार्यकर्ताओं की सहमति के आधार पर किया जाता है। और आज के बैठक में हम सभी कांग्रेसजन ऊर्जावान कार्यकर्ताओं का चयन करते हुए मजबूत बूथ कांग्रेस कमेटी का गठन करेंगे।

महापौर ने आगे बताया कि प्रत्येक बूथ में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी सभी बूथों में महिलाओं को ज़िम्मेदारी सुनिश्चित कर महिला कार्यकर्ताओं को भी ज़िम्मेदारी दी जाएगी। मनोज साहू ने संबोधित करते हुए कहा कि भूपेश सरकार की योजना आम लोगों के लिए किसानों के लिए व्यापारियों के लिए मज़दूरों के लिए ही बनायी गई है और इन सभी योजनाओं से आम लोगों को बहुत लाभ हुआ है इन सभी योजनाएँ को जन जन तक पहुंचाने कार्यकर्ताओं से अपील किया एवं सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया।

बूथ नं 61 अध्यक्ष भरत साहू,उपाध्यक्ष दिनेश देवांगन, रोहित ध्रुव दुष्यंत यादव कोषाध्यक्ष प्रेम नाथ साहू,सचिव राजू ध्रुव,गौतम साहू/रामाधीन, गीता सिन्हा,सह सचिव चूरामन पटेल,परमानंद ध्रुव लीना ध्रुव,सो।मिडिया समन्वय उदेशंकर साहू, कार्यकारणी सदस्य कोमल ठाकुर,सोहद्रा बाई,गायत्री देवांगन,हेमंत निर्मलकर,सुरेखा साहू,दिनेश ध्रुव,गोपेश्वर साहू,दीनू साहू,पुलकित ध्रुव। बूथ नं।62 अध्यक्ष देवमत साहू, उपाध्यक्ष उर्मिला साहू,मानक यादव,नवीन कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष गौतम साहू/रितु साहू,सचिव संतोषी ढीमर,मोती सिन्हा,दौलत साहू,सहसचिव प्रीति यादव,ठाकुर राम देवांगन, रोहित साहू,सो।मीडिया समन्वयक मोनू सिन्हा, कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार सिन्हा,तोरन साहू,लक्ष्मी साहू,गिरधारी साहू,आधारी साहू, हरिराम सिन्हा,चुरामन साहू,पेमन ध्रुव,प्रकाश साहू। बूथ नं।63 अध्यक्ष शिवशंकर साहू,उपाध्यक्ष जगदेव साहू,टिकेश्वरी ध्रुव,दिलीप यादव, कोषाअध्यक्ष अजीत साह,सचिव दुरपति यादव,गोपी देवांगन, बोधीराम साहू, सहसचिव बिसाहू राम साहू,राजू राम साहू,ऊषा शर्मा,सो।

मिडिया समन्वयक पेश कुमार निर्मलकर, कार्यकारिणी सदस्य तरुण यादव,गेंद देवांगन, तेज प्रकाश साहू,नंद देवांगन,सविता ध्रुव,पवन ढीमर, नंदकुमार साहू,संतोष ढीमर,राकेश निर्मलकर, बूथ नं। 64 अध्यक्ष नरेंद्र कांकेरिया, उपाध्यक्ष लक्ष्मी सिन्हा,दिलीप गोस्वामी, कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार साहू, सचिव अहमद खान, रामेश्वर सिन्हा,मणि साहू,सहसचिव सत्यनारायण सिन्हा,दीप्ति साहू, चंद्रकांत साहू, सो।मिडिया समन्वयक अंकुश पुरी गोस्वामी, कार्यकारिणी सदस्य विक्रम साहू, अभिषेक पुरी, किशन साहू, शीतल साहू, बब्ला ध्रुव,राम ढीमर,खिलेश्वर साहू,सोमन देवांगन,देवेन्द्र नांगरची,

बैठक में मुख्य रूप से ज़ोन प्रभारी महापौर विजय देवांगन ,जोन अध्यक्ष मनोज साहू,गजेंद्र कुंभकार,चितेंद्र साहू,बलराम साहू एवं तीनो गांव से दिलीप साहू,रितु साहू ,रामकुमार सिन्हा, बिसाहू साहू, दिनेश पुरी, राजू ध्रुव, मुकेश साहू, नंदू यादव, राजेन्द्र कुमार, जानू साहू, मन्नू यादव, चंद्रहास साहू, फक्कीर चंद,परमानंद आडील,गौतम साहू,विक्रम साहू, अभिषेक साहू, नवीन सिन्हा,अंकुर पुरी गोस्वामी, गिरीश यादव, दीनू साहू, यश निर्मलकर, नमन, खिलेन्द्र साहू, मोनू बघ्घा सहित कार्यकर्ता गण अधिक संख्या मे उपस्थित थे।

कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा के दुष्प्रचार का सामना करने तैयार: लालवानी

धमतरी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार विधानसभा वार प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम के अंतर्गत गुरूवार को छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष मोहन लालवानी के प्रभार क्षेत्र भानुप्रतापपुर विधानसभा में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर को लेकर छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष मोहन लालवानी ने कहा कि कांग्रेस लगातार चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा के दुष्प्रचार का सामना करने तैयार हैं। पार्टी के सिद्धांतों, राज्य सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी सबको दी जा रही है। उन्होंने ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि, हम विरोधियों को कमजोर नहीं मानते, इसलिए पूरी गंभीरता के साथ पार्टी की तैयारियों में जुट गए है। प्रशिक्षण शिविर में समस्त कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनहितैषी कार्यों को दूरस्थ अंचल के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। शिविर में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में पुन: कांग्रेस की सरकार बनाने के लिये चुनावी तैयारी में जूटने की बात कही।

एनएच निर्माण में धांधली को लेकर ननकीराम कंवर धरने पर बैठे

■ प्रशासन पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप

कोरबा। ननकीराम कंवर ने एनएच निर्माण में धांधली को लेकर अफसरों पर मुआवजा कम देने और रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। कोरबा और चांपा के बीच एनएच का निर्माण चल रहा है। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता ननकीराम कंवर ने निर्माण कार्य को लेकर प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं।

जमकर नोकझोंक- एनएच और प्रशासन के खिलाफ रोड जाम कर विधायक एवं पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। कंवर और प्रशासन की टीम के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। नगर पालिक निगम के नेता प्रतिपक्ष के कारण अग्रवाल भी मौजूद थे। पुलिस की मौजूदगी में तहसीलदार से उनकी भी जमकर बहस हुई। कोरबा एसडीएम पर मुआवजा में गड़बड़ी और रिश्वतखोरी का आरोप विधायक और ग्रामीणों ने लगाया। इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। उचित मुआवजे की मांग और बारिश में लोगों के घर ना तोड़े जाने को लेकर ग्रामीण चक्का जाम पर बैठे थे।

ननकीराम कंवर का बिना मुआवजा मकान तोड़ने का आरोप-राष्ट्रीय राजमार्ग कोरबा चांपा निर्माण को लेकर एनएच पर मनमानी का आरोप है। देखने में आ रहा है कि बिना मुआवजा दिए मकान तोड़े जा रहे हैं। जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने की है। एक दिन पहले देर शाम कुछ मकानों को जिनके घर के मालिक काम में गए हुए थे और ताला बंद था, ऐसे मकानों को बिना नोटिस व मुआवजा दिए तोड़ दिया गया

है। जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सुबह से ही ग्रामीण रोड में इकट्ठा होने लगे हैं। जब तक मुआवजा और अन्य मांगों पर सहमति नहीं बन जाती हम आंदोलन जारी रखेंगे।

शिविर लगाने की बात पर आंदोलन हुआ समाप्त- विधायक ननकीराम कंवर ने मौके पर पहुंचते ही रोड को जाम कर दिया। जिसके बाद सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। चक्का जाम की सूचना पर उरगा पुलिस और तहसीलदार अपने टीम के साथ पहुंचे और चक्का जाम पर बैठे विधायक और ग्रामीणों से बात करने की कोशिश की, ग्रामीणों का यह आंदोलन काफी देर तक चला। देर शाम को गांव में शिविर लगाकर मुआवजा प्रकरण के साथ ही अन्य मांगों पर संवेदनशीलता के साथ निराकरण करने की बात हुई।जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किये जाने का आश्वासन अधिकारियों ने दिया है।

केन्दीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ आना कांग्रेस के लिए शुभ -राकेश ठाकुर

पाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुरुवार को अपने दुर्ग दौरे के दौरान दिए गए कांग्रेस को उखाड़ फेंकने, सहित अन्य बयानों पर पलटवार करते हुवे किसान नेता एवं डायरेक्टर अपेक्स बैंक छत्तीसगढ़ शासन राकेश ठाकुर ने कहा है कि 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाटन सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में सभा आयोजित किया था जिसमें उन्होंने अबकी बार 65 पार का नारा दिया था लेकिन भाजपा 15 सीट पार नही कर पाया था और कांग्रेस ने 65 सीट पार करते हुवे 68 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज किया था अब आगामी कुछ माह में फ़िर विधानसभा चुनाव आने वाला है तो अमित शाह भाजपा कार्यकर्ताओं की छोटी मोटी सभा आयोजित कर अब छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे है लेकिन सच्चाई तो यह है कि अमित शाह छत्तीसगढ़ आ कर जो भी बोलते है उनका विपरीत असर छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है इसका साफ मतलब है कि छत्तीसगढ़ अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पहले से और अधिक सीटों पर जीतकर पुन: सरकार बनाएगी वहीं भाजपा हवा-हवाई राजनीति करने के चक्कर में खुद छत्तीसगढ़ से उखड़ जाएगी।

श्री ठाकुर ने आगे कहा कि 15 साल छत्तीसगढ़ में राज करने वाली भाजपा छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कदम पड़ने से 15 सीटों पर सिमट गई थी वहीं इस बार चुनावी समय मे फ़िर छत्तीसगढ़ आ कर अमित शाह भाजपा के सूपड़ा साफ करने की नींव रख कर गए है बाकी भाजपा को बर्बाद करने का कार्य अब कुछ दिनों बाद नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ कर करेंगे।

छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाने के लिए कांग्रेस कर रही मेहनत

कांकेर। आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में सरकार के कामों को आंकड़ों के साथ कार्यकर्ताओं को बताया गया। ताकि कार्यकर्ता मैदानी स्तर पर जाए तो उन्हें सरकार के योजनाओं की सफलता आंकड़ों के साथ पता रहे।

प्रशिक्षकों के मुताबिक प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने नेताओं और कार्यकर्ताओं को बूथ में पहुंचकर मतदाताओं को छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितकारी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करना है। वहीं भूपेश सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देनी है। ट्रेनर्स से कांग्रेस पदाधिकारियों को बूथ लेवल में पहुंचकर जनता से सीधा संवाद बनाए रखने की बात कही।

विधायक, शिशुपाल सोरी ने कहा यह चुनाव पार्ट है, प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी और उसके आंकड़ें कार्यकर्ताओं के साथ साझा किए गए।ताकि आगामी समय में होने वाले विधानसभा

चुनाव में जनता के बीच पहुंच कर सरकार द्वारा किये गए कार्यो की जानकारी दी जा सके। इस प्रशिक्षण शिविर में में विधायक, पूर्व सांसद , पूर्व विधायक,सांसद प्रत्याशी, स्थानीय प्रदेश,जिला,ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, जोन, सेक्टर के अध्यक्ष, प्रभारी, पंचायत, निकाय, मंडी, सहकारी समिति के पदाधिकारी, निगम मंडल बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, पार्षद,मनोनीत पार्षदगण, सेवादल, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई एवं अन्य मोर्चा , समस्त प्रकोष्ठ और विभाग के पदाधिकारीगण, समन्वय समिति के सदस्य, आईटीसेल के पदाधिकारी को सम्मलित किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में संसदीय सचिव ,कांकेर विधायक शिशुपाल शोरी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस महामंत्री पीयूष कोसरे, पूर्व विधायक शंकर ध्रुवा सहित काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

पुण्यतिथि पर भाजपाइयों ने डॉ. श्यामा प्रसाद को दी श्रद्धांजलि

नगरी। भारतीय शिक्षाविद,चिंतक,प्रखर राष्ट्रवादी राजनेता,भारतीय जनसंघ के संस्थापक एवं स्वतंत्रता के बाद देश की एकता एवं अखंडता के लिए प्रथम बलिदानी योद्धा डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर 23जून को वार्ड क्रमांक 2 में स्थित प्रतिमा पर पूजा अर्चना कर एवं माल्यार्पण कर भाजपा नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया।इस दौरान सिहावा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्रवण मरकाम,भाजपा के जिला महामंत्री प्रकाश बैस,जिला मंत्री राजेंद्र गोलछा,मंडल अध्यक्ष मोहन नाहटा,पूर्व जिला महामंत्री एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष नागेंद्र शुक्ला,नगर पंचायत के अध्यक्ष आराधना शुक्ला, नगर पंचायत उपाध्यक्ष अजय नाहटा,जनपद अध्यक्ष दिनेश्वरी नेताम,अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष महेंद्र नेताम, डॉ के एस शांडिल्य, मंडल के महामंत्री हृदय साहू, भाजयुमो के अध्यक्ष एवं पार्षद सुनील निर्मलकर, पार्षद विनीता कोठारी, महिला मोर्चा के मंडल महामंत्री चेलेश्वरी साहू, नरेश राव गायकवाड़ सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सड़क हादसे में बाल-बाल बचे भाजपा नेता केदारनाथ

कोरबा। कोरबा निवासी और वरीष्ठ भाजपा नेता केदारनाथ अग्रवाल के साथ उनका परिवार एक सड़क दुर्घटना में बाल-बाल बच गया। केदारनाथ अग्रवाल अपनी पत्नी, पोती और ड्राइवर के साथ शादी समारोह में शामिल होने कटघोरा गए हुए थे। वहां से वापसी के दौरान उनकी कार दर्री स्थित सीएसईबी कॉलोनी के नजदीक जूनियर क्लब के पास दूसरी कार से टकरा गई। वरिष्ठ नेता केदारनाथ अग्रवाल मध्यरात्रि को उस समय बाल-बाल बच गए। जब उनकी कार को सामने से आ रही एक कार ने जबरदस्त टक्कर मार दी। केदारनाथ अग्रवाल पत्नी, पोती और ड्राइवर के साथ कटघोरा से एक शादी समारोह में शामिल होने के पश्चात वापस लौट रहे थे। तभी सीएसईबी कॉलोनी दर्री के जूनियर क्लब के पास उनकी कार पहुंची ही थी। तभी सामने से एक कार दुरुतगति से आई और अनियंत्रित होकर उनकी कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। सुखद संयोग रहा कि केदारनाथ अग्रवाल की गाड़ी के सभी एयर बैग खुल गए और कार में मौजूद सभी लोगों की जान बच गई।

परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने बसों के काटे चालान

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। कल से प्रदेश भर में स्कूल खुलने वाले हैं। स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए लगाए गए वाहनों की जांच के लिए पुलिस और परिवहन अधिकारियों के मार्गदर्शन में जिले में संचालित स्कूलों के बसों का परमिट, लाइसेंस, फिटनेस, इंश्योरेंस, प्रदूषण सर्टिफिकेट, गाड़ी में फायर सेफ्टी समान, फर्स्ट एड किट, गाड़ी की पार्किंग लाइट, इंडिकेटर इत्यादि की जांच की गई। जिसमें कल्याणिका स्कूल, भारत माता पब्लिक स्कूल, ओरिएंट स्कूल, स्ह स्कूल की बसों की जांच की गई। गाड़ियों के संपूर्ण दस्तावेज रखने और सुरक्षा संबंधी संपूर्ण सामान रखने, धीरे चलने के निर्देश दिए गए। सामान्य कमियों के कारण नौ वाहनों के चालान काटे गए। 8600 रुपये समन शुल्क वसूला गया। तो छत्तीसगढ़ से मध्यप्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाली लंबी दूरी की बसों की भी जांच की गई। जिसमें खुद जिला परिवहन अधिकारी विवेक सिन्हा और उनके स्टाफ के साथ पिछले 24 घंटों से वाहनों की जांच में लगे हुए हैं।

इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अमित का नाम दर्ज

भिलाई। हाउसिंग बोर्ड कैलाश नगर निवासी विजय सिंह के पुत्र अमित सिंह ने इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। अमित सिंह ने पिछले साल बनाएं 30 सेकंड में 46 पुशअप्स का स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ कर नया रिकॉर्ड 30 सेकंड में 52 पुशअप्स मारकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। अमित की इस उपलब्धि से उनका पूरा परिवार खुश है। अमित सिंह एक ऐसे होनहार खिलाड़ी हैं इनके नाम के आगे कई रिकॉर्ड दर्ज है इससे पहले अमित ने 1 मिनट में सबसे ज्यादा 84 पुशअप्स मारने का रिकॉर्ड पिछले साल इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया था। आर्म्रेसलिंग में गोल्ड मेडलिस्ट साथ ही साथ मोस्ट पुशअप्स इन वन टाइम ग्वालियर में आयोजित होने वाले मैच में 183 पुशअप्स मारकर अमित ने ये सारी उपलब्धियां बिना किसी सहयोग के व बिना किसी विशेष ट्रेनिंग के खुद के प्रयास से हासिल की है। अमित ने कहा कि अगर शासन सहयोग करेगी तो ओलंपिक में भी मेडल लाकर छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाएंगे।

पीईटी व पीपीएचटी की प्रवेश परीक्षा आज

कोरबा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित होने वाले पीईटी व पीपीएचटी परीक्षा जिले में 25 जून 2023 को दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली में पीईटी की परीक्षा पूर्वान्ह 09 बजे से 12.15 बजे तक और द्वितीय पाली में पीपीएचटी की प्रवेश परीक्षा अपरान्ह 2 बजे से 5.15 बजे तक आयोजित किया जायेगा। जिले में पीईटी की परीक्षा हेतु 02 एवं पीपीएचटी परीक्षा के लिए 03 केन्द्र बनाया गया है। पीईटी की परीक्षा में कुल 1006 परीक्षार्थी शामिल होंगें। इसी प्रकार पीपीएचटी परीक्षा में कुल 1516 परीक्षार्थी शामिल होंगें। कलेक्टर संजीव कुमार झा के दिशा-निर्देश में परीक्षा के सुचारू संपादन व जिला कोषालय कोरबा से परीक्षा केन्द्र के लिए गोपनीय सामग्री प्राप्त करने व परीक्षा समाप्ति पश्चात उत्तर पुस्तिका एवं अन्य सामग्री अपने निगरानी में सील्ड कराकर समन्वयक केंद्र में जमा करने हेतु विभिन्न अधिकारियों को प्रशासनिक पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

पूर्व मंत्री रामविचार नेताम ने मंच से टिकट की दावेदारी की पेश

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले ही चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है। रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र के रामचंद्रपुर में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिसमें मंच से छत्तीसगढ़ के कद्दावर आदिवासी नेता पूर्व गृह मंत्री रामविचार नेताम ने विधायक बृहस्पति सिंह पर जमकर निशाना साधा । इस दौरान रामानुजगंज विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर दिया है। क्या भाजपा से रामविचार नेताम को रामानुजगंज विधानसभा से टिकट मिलेगा या फिर पार्टी किसी दूसरे चेहरे पर भरोसा करेगी ये अभी साफ नहीं है।इसी बीच नेताम के समर्थक भी नेताम को टिकट देने की मांग कर रहे हैं।

भाजपा के कद्दावर नेता हैं नेताम

रामविचार नेताम भाजपा के कद्दावर आदिवासी चेहरा हैं। जिनकी पहचान प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक है। नेताम

छत्तीसगढ़ सरकार में गृहमंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही राज्यसभा सांसद भी हैं। रामविचार नेताम सन 1990 से लेकर 2013 तक विधायक रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार थी। उस दौरान अहम मंत्रालय के मंत्री भी रहे हैं। पहले यह विधानसभा पाल के नाम से जाना जाता था।

क्या है सीट का गणित

रामानुजगंज विधानसभा में पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस का कब्जा है। बृहस्पति सिंह विधायक हैं। बीजेपी में टिकट के कई दावेदार हैं। लेकिन रामविचार नेताम रामानुजगंज में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा हैं। टिकट के सबसे मजबूत दावेदार भी हैं। हालांकि पार्टी किसे टिकट देकर प्रत्याशी बनाएगी यह तो आने वाले समय ही बताएगा।

पिछली बार मिली थी हार

2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रामकिशन सिंह को टिकट दिया था। लेकिन बीजेपी के ही एक बागी प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतर गए। बीजेपी के अंदर जमकर भीतरघात हुआ। इससे बीजेपी के वोटों का बिखराव हो गया।जिसके कारण कांग्रेस के प्रत्याशी बृहस्पति सिंह को बड़ी जीत मिली।

रामविचार नेताम ने दी चुनौती

लाभार्थी सम्मेलन के दौरान मंच से नेताम ने जहां केंद्र सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों का बखान किया तो वहीं वर्तमान विधायक बृहस्पति सिंह पर भी जमकर निशाना साधा। अब समय आ गया है। पिछले साढ़े चार साल से क्षेत्र की जनता त्रस्त है। कांग्रेस की सरकार ने गौठान के नाम पर भ्रष्टाचार किया है। इसलिए आने वाले चुनाव में कांग्रेस को मिलकर जवाब देने का समय आ गया है।

लाभार्थी सम्मेलन में बीजेपी ने जहां अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। वहीं दूसरी तरफ बातों-बातों में रामविचार नेताम ने हुंकार भरके एक बार फिर टिकट की दावेदारी पेश की।जिसके बाद ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं नेताम खुद को इस सीट से दावेदार मान रहे हैं।

निगम की काम से हटाने की सख्त चेतावनी के बाद स्वच्छता दीदियों का प्रदर्शन खत्म

धमतरी। जिले में 4 दिनों से हड़ताल कर रहे स्वच्छता दीदियों ने हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने का फैसला लिया है। ये वापसी नगर निगम के सख्त रवैये के बाद हुई है। स्वच्छता दीदियों ने कलेक्टर दर पर भुगतान की मांग को लेकर 20 जून से हड़ताल शुरू किया था।। पहले इसे 3 दिन का आंदोलन बताया गया। लेकिन तीसरे दिन इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन कर दिया गया।

23 जून को प्रदेश के बाकी हिस्सों में स्वच्छता दीदियों ने हड़ताल खत्म कर दिया था। लेकिन धमतरी में वे चौथे दिन भी हड़ताल पर बैठे रहे। इसके बाद धमतरी नगर निगम ने हड़तालियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए काम से हटाने की चेतावनी दी। इसके बाद स्वच्छता दीदियों ने हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने का ऐलान किया।हड़ताल खत्म होने से शहर में ठप हो चुकी सफाई व्यवस्था को वापस पटरी पर लौटने से निगम और शहर वासियों को राहत मिलेगी। अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर जिले की स्वच्छता दीदियां पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर थी। प्रदेश संघ से चर्चा के बाद हड़ताल को स्थगित किया गया है।

ये है स्वच्छता दीदियों की मांग- टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए 2017 से स्वच्छता दीदी काम कर रही हैं। यह वाहन, रिक्शा के माध्यम से घर-घर जाकर कचरा कलेक्शन करती हैं, जिसे मणीकंचन केंद्र में लाकर डिस्पोज किया जाता है। इन्हें 6000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। महिलाएं बताती हैं कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। यदि किसी कारणवश बीमार पड़ जाती हैं तो उस दिन का पेमेंट भी कट जाता है। गंदगी के बीच कई स्वच्छता दीदी बीमार पड़ जाती है। जिनका खर्चा खुद को उठाना पड़ता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

रंगमंच सज चुका है, नाटकमंडली एकत्रित हो चुकी: अनुराग ठाकुर

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से विपक्षी एकता को लेकर तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रंगमंच सज चुका है। नाटक मंडली भी एकत्रित हो चुकी है। भाजपा नेताओं ने वर्ष 2024 के आम चुनाव में उसके खिलाफ विपक्षी दलों के एकजुट होने की कोशिशों की आलोचना करते हुए पटना की बैठक को 'स्वार्थ का गठबंधन', 'नाटक' और 'तस्वीर खिंचवाने' का अवसर करार दिया है। विपक्ष की बैठक पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि रंगमंच सज चुका है, नाटकमंडली एकत्रित हो चुकी है। कैसे उस मंच पर एकत्रित हो गए जहां ममता बनर्जी कांग्रेस को कहती है बंगाल छोड़ दो, अखिलेश कहते हैं यूपी छोड़ दो, लालू-नीतीश कहते हैं बिहार छोड़ दो। तो कांग्रेस क्या गठबंधन में कुर्सियां लगाने के लिए रह जाएगी? केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर मंच सज गया है। तमाशा करने वाले एकजुट हो गए हैं, पात्र तय किए जा रहे हैं, अब तमाशा होगा।

हम इंदिरा से नहीं, शासन से लड़ रहे थे : ललन सिंह

पटना। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि आज इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति है। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि वे क्या बोलेंगे, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि 1974-1975 में हमारी लड़ाई इंदिरा गांधी से नहीं, बल्कि शासन से था। आज की स्थिति 1974-75 से भी बदतर है। उन्होंने कहा कि देश में आज इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति है। उन्होंने कहा कि उस समय प्रेस की आजादी थी। आज इनकी नियंत्रण में प्रेस तो है ही साथ ही साथ सारे संवैधानिक संस्थाओं पर भी इनका नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज अगर आपके खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो सीधे उसके यहां छापा पड़ने लगता है। उन्होंने दावा किया कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया।

लोकतंत्र बचाने के लिए हमें साथ आना होगा : संजय राउत

मुंबई। पटना में शुक्रवार को विपक्षी दलों की बैठक हुई। बैठक का हिस्सा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद सभी दलों ने एक साथ चुनाव लड़ने की बात कही है। सभी ने एक स्वर से भाजपा पर निशाना भी साधा। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि यदि 2024 के बाद लोकतंत्र को जीवित रखना है तो राजनीतिक नेताओं को राष्ट्रहित के लिए बड़ा दिल दिखाना होगा। अगर सभी एक साथ आएंगे तो इससे मतदाताओं में विश्वास पैदा होगा। संजय राउत ने कहा कि बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा है कि, अगर 2024 में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो यह आखिरी चुनाव होगा, इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें (विपक्षी दलों) को एकजुट रहना होगा और चुनाव लड़ना होगा। यह टिप्पणी विपक्षी दलों द्वारा पिछले दिन पटना में एक महत्वपूर्ण एकता बैठक आयोजित करने के बाद आई है।

पीएम भारत में हिंदू-मुस्लिम करते हैं और बाहर जाकर लोकतंत्र की बात करते हैं

पटना। विपक्षी दलोंकी बैठक में हिस्सा लेने पटना आईं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी जब भारत में रहते हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हैं और जब भारत से बाहर जाते हैं तो लोकतंत्र की बात करते हैं और उनकी वाहवाही होती है। वहां से जब वापस भारत आते हैं तो यहां आकर हिंदू - मुस्लिम करना शुरू कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनको जो इज्जत मिलती है वह उनको नहीं मिलती बल्कि गांधी के हिंदुस्तान को मिलती है। आखिर यह कैसा लोकतंत्र है? महबूबा ने कहा कि पीएम के हिंदू-मुस्लिम करने से न सिर्फ देश को नुकसान होता है बल्कि इसमें जम्मू कश्मीर का काफी नुकसान होता है। एक मुस्लिम बहुल राज्य होते हुए भी हमने मुश्किल दिनों में हिंदुस्तान से हाथ मिलाया। हमें मालूम है की यह एक धर्मनिरक्ष देश है।

शाह की सर्वदलीय बैठक पर कांग्रेस ने साधा निशाना

नई दिल्ली। मणिपुर में फैली हिंसा के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक से पहले ही कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। शनिवार को भाजपा सरकार पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार मणिपुर के लोगों को विफल कर रही है। कांग्रेस नेता ने मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को ट्विटर पर कहा, मणिपुर में आग लगने के 52 दिन बाद गृहमंत्रालय ने आखिरकार शनिवार दोपहर 3 बजे मणिपुर पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाना उचित समझा। कांग्रेस नेता ने मणिपुर की स्थिति पर पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा, प्रधानमंत्री इतने समय तक चुप रहे। इसे राष्ट्रीय पीड़ा के प्रदर्शन के रूप में इंफाल में आयोजित किया जाना चाहिए था।

केंद्रीय गृह मंत्री ने अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की

जम्मू कश्मीर से अमित शाह ने आतंकवाद पर किया प्रहार

श्रीनगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान जम्मू और श्रीनगर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया, सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और आतंकी हमले के पीड़ितों से मुलाकात की। देखा जाये तो गृह मंत्री का यह दौरा कई मायनों में अहम रहा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस साल जनवरी में जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के एक गांव पर हुए आतंकवादी हमले में जीवित बचे लोगों से मुलाकात की और उन्हें हरसंभव सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने बताया कि अमित शाह ने राजौरी आतंकवादी हमले में जीवित बचीं श्रीमती सूरज शर्मा और उनके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि उनका साहस और वीरता आतंकवाद के खतरे को समाप्त करने में भारत की ताकत के स्तंभ हैं। अमित शाह ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। हम आपको बता दें कि सूरज शर्मा एक विधवा हैं। इस हमले में उनके दो बेटे दीपक और प्रिंस की मौत हो गयी थी। वह परिवार में अकेली जीवित बची हैं। उनके साथ सुशील और उनकी पत्नी भी थी जिन्होंने इस हमले में अपना बच्चा खो दिया था। इसके अलावा हमले में घायल हुए पवन शर्मा भी मौजूद थे। इस हमले में पवन का भाई मारा गया था।

इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर एक बैठक में जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के अलावा खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और नागरिक प्रशासन के शीर्ष अधिकारी श्रीनगर में आयोजित इस बैठक में शामिल हुए। अमित शाह ने इस बारे में ट्वीट किया, ''श्रीनगर में व्यापक सुरक्षा समीक्षा की। यह देखकर खुशी हुई कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एजेंसियां बहु-आयामी दृष्टिकोण अपना रही हैं। जम्मू-कश्मीर में निरंतर शांति और स्थिरता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा निर्धारित प्रमुख लक्ष्यों में से एक है।'' सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में गृह मंत्री ने सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और उन्हें केंद्रशासित प्रदेश में सुरक्षा स्थिति की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि अमित शाह को अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ नियंत्रण रेखा पर मौजूदा स्थिति से अवगत कराया गया। सूत्रों ने बताया कि

केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दिए। यह सुरक्षा समीक्षा बैठक वार्षिक अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से कुछ दिन पहले हुई है। हम आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र में 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तीर्थस्थल के लिए एक जुलाई से यह यात्रा शुरू हो रही है, जो 31 अगस्त को समाप्त होगी। नयी दिल्ली में नौ जून को आयोजित एक बैठक में शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की प्राथमिकता सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करना है। उन्होंने तब अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर में पूरे तीर्थयात्रा मार्गों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। यह तीर्थयात्रा जम्मू और कश्मीर में दो मार्गों - बालटाल और पहलगाम से होती है। सभी तीर्थयात्रियों को आरएफआईडी कार्ड दिए जाएंगे ताकि उनके वास्तविक स्थान का पता लगाया जा सके और सभी को पांच लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि तीर्थयात्रियों को ले जाने वाले प्रत्येक जानवर के लिए 50,000 रुपये का बीमा कवर होगा। सूत्रों के मुताबिक, पिछले साल करीब 3.45 लाख लोगों ने पवित्र हिम शिवलिंग के दर्शन किए थे और इस बार यह संख्या पांच लाख तक पहुंच सकती है।

इस बीच, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में हुए सर्वांगीण विकास पर प्रकाश डालते हुए कश्मीरी युवकों से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि वे पत्थर उठाने के बजाय कलम और लैपटॉप साथ रखें। अमित शाह ने श्रीनगर में तीन-दिवसीय वितस्ता महोत्सव के उद्घाटन के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग जम्मू-कश्मीर का केवल पिछले चार दशक का इतिहास जानते हैं, वे सोचते हैं कि यह एक विवादित या अशांत क्षेत्र है। उन्होंने कहा, ''लेकिन कश्मीर एक ऐसी भूमि है, जिसने अतीत में रक्तपात का दंश झेला है और विजयी होकर अधिक स्थिर एवं शांतिपूर्ण बनकर उभरी है।

उन्होंने कहा कि इस भूमि ने पिछले तीन से चार दशक में आतंकवाद के कारण लगभग 40,000 मौतें देखी हैं, लेकिन आज वही कश्मीर वितस्ता महोत्सव मना रहा है और आगे बढ़ रहा है। गृहमंत्री ने इस अवसर पर कश्मीर के युवाओं से घाटी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में सोचने का आह्वान किया। उन्होंने अतीत में पथराव वाले विरोध प्रदर्शनों का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा, ''जिन्होंने आपके हाथ में हथियार और पत्थर सौंपे, वे कभी भी आपके शुभचिंतक नहीं थे। आपके हाथों में कलम, लैपटॉप और किताबें होनी चाहिए, न कि पत्थर। उन्होंने कश्मीरी संस्कृति की तुलना वितस्ता (झेलम) नदी से की और कहा, ''अगर कोई कश्मीर का सही इतिहास जानता है, तो नफरत कभी उसका हिस्सा नहीं रही है। जो भी कश्मीर आया उसका खुले दिल से स्वागत किया गया। गृहमंत्री ने 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से जम्मू-कश्मीर में सर्वांगीण विकास पर भी प्रकाश डाला। निरस्त हो चुका यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। हम आपको बता दें कि इस महोत्सव का आयोजन प्रसिद्ध डल झील के किनारे स्थित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) के मैदान पर किया जा रहा है। यहां आये प्रतिभागियों से प्रभासाक्षी संवाददाता ने बातचीत की तो सभी ने कश्मीर के बदलते माहौल पर अपनी खुशी जताई। जम्मू-कश्मीर के अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने श्रीनगर के मध्य में स्थित प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी। अधिकारियों के मुताबिक, इस स्मारक का निर्माण श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किया जा रहा है और यह उन शहीदों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। आधारशिला रखने के तुरंत बाद अमित शाह उपराज्यपाल के आधिकारिक आवास राजभवन पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि समारोह के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे, लेकिन पार्क के अंदर और आसपास की दुकानें खुली रहीं तथा यातायात भी मुख्यत: सामान्य रहा।

भाजपा को हराने हर विपक्षी दल कुर्बानी देने को तैयार : नीतीश

पटना। पटना में गैर भाजपा दलों की बड़ी बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई। इस बैठक में हिस्सा लेने 15 विपक्षी दलों के शीर्ष नेता पटना स्थित सीएम आवास पहुंचे थे। सभी नेताओं ने एक स्वर में भाजपा के खिलाफ एकजुट होने और संघर्ष करने का एलान किया। यह बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर आयोजित की गयी। सीएम नीतीश कुमार ने इस बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि भाजपा को हराने के लिए विपक्षी दल किस तरह तैयारी में जुटेंगे।

शुक्रवार को पटना के एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई। गुरुवार से ही विपक्षी दलों के नेता पटना पहुंचने लगे थे। सीएम आवास के नेक संवाद में शुक्रवार को करीब साढ़े तीन घंटे तक बैठक चली। जिसमें 15 दलों के शीर्ष नेता व पार्टी अध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने और केंद्र की सत्ता से दूर रखने को लेकर सबने अपनी-अपनी राय रखी। बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार समेत अन्य नेताओं ने बैठक व आगे की रणनीति को लेकर अपनी-अपनी बात संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस के जरिए सामने रखी।

सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सभी दलों की ये राय बनी है कि अभी जो पार्टी सत्ता में है वह देशहित में काम नहीं कर रही है। पूरे इतिहास को बदले जाने की तैयारी है। आजादी की लड़ाई को भुलवा देने की कोशिश की जा रही है। सबने एकमत होकर तय किया है कि कोई चुनौती आएगी तो इसका मिलकर सामना करेंगे। कुछ ही दिनों के बाद एक और बैठक होगी जिसमें आगे की योजना पर सहमति बनेगी।

बता दें कि नीतीश कुमार व लालू यादव समेत कई अन्य नेताओं ने ये माना है कि वोटों के बिखराव से भाजपा को फायदा होता है। एक लोकसभा सीट पर भाजपा के खिलाफ कई विपक्षी दलों के उम्मीदवार उतार दिए जाते हैं जिसका फायदा भाजपा को मिलता है। वोटों के इन्हीं बिखराव को रोकने की पूरी तैयारी में नीतीश कुमार विपक्षी दलों के नेताओं के साथ लगे हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी अपने संबोधन में इन्हीं वोटों की बात कही।

राजद सुप्रीमो लालू यादव ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि हमें एकजुट होकर लड़ना है। वोट हमारा है और इसमें बिखराव होने से भाजपा चुनाव जीत रही है। कांग्रेस ने भी एकजुट होकर लड़ने और भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की बात कही। शरद पवार, ममता बनर्जी समेत अधिकतर नेताओं ने खुलकर ये बात कही है।

गिरिराज सिंह ने विपक्ष की बैठक का उड़ाया मजाक

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को मेगा विपक्षी एकता बैठक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्षी नेता एक फोटो सत्र के लिए और बिहार के लिट्टी चोखा का आनंद लेने के लिए पटना में एकत्र हुए। बीजेपी मंत्री ने कहा कि विपक्ष की बैठक से कुछ नहीं निकलेगा। गिरिराज सिंह ने मेगा मीटिंग पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये सब चाय पार्टी पर मिले, लिट्टी खाए। बता दें कि लालू यादव ने राहुल गांधी से कहा कि वह अपनी दाढ़ी कटवा लें और शादी कर लें। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के खिलाफ गठबंधन बनाने की रणनीति तैयार करने के लिए शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेजबानी में विपक्ष की एक बड़ी बैठक पटना में हुई। कल 17 विपक्षी दलों की बैठक हुई लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिमला में दो दिवसीय बैठक करने का फैसला किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि यह वास्तव में एक फोटो सत्र था।

खेल
प्रमुख समाचार

पुजारा को टीम से बाहर करने से खफा हुए गावस्कर

मुंबई। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने चेतेश्वर पुजारा को 'बलि का बकरा' बनाने और घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने वाले सरफराज खान को अगले महीने वेस्टइंडीज में होने वाले दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला की टीम से नजरअंदाज करने के लिए राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की आलोचना की है।

सरफराज को टीम में जगह नहीं देने से खफा गावस्कर ने रणजी ट्रॉफी के आयोजन पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि टेस्ट टीम का चयन में देश के शीर्ष घरेलू टूर्नामेंट के प्रदर्शन को नजरअंदाज कर इंडियन प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार किया जा रहा है। गावस्कर ने कहा, ''सरफराज खान पिछले तीन सत्र से लगभग 100 की औसत से रन बना रहा है। उसे टीम में जगह बनाने के लिये क्या करना होगा? हो सकता है कि उसे अंतिम एकादश में जगह ना मिले लेकिन टीम में उनका चयन तो होना ही चाहिए था।'' इस पूर्व दिग्गज ने कहा, ''उसे ऐसा लगना चाहिए कि उसके प्रदर्शन को सराहा जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो, रणजी ट्रॉफी खेलना बंद कर दें। आईपीएल में अच्छा खेलकर अगर आप टेस्ट टीम में जगह बना लेंगे तो फिर रणजी ट्रॉफी का कोई फायदा नहीं है।'' सरफराज ने 2022-23 रणजी ट्रॉफी में तीन शतकों की मदद से छह मैचों में 92.66 की औसत से 556 रन बनाए। इस 25 साल के दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 2021-22 रणजी सत्र में 122.75 की औसत से 982 रन बनाए थे, जिसमें चार शतक शामिल थे।

सरफराज ने अब तक 37 प्रथम श्रेणी मैचों में 79.65 की औसत से 3,505 रन बनाए हैं, जिसमें 13 शतक शामिल हैं। उन्होंने पुजारा को टेस्ट टीम से बाहर किये जाने पर कहा कि सोशल मीडिया पर इस खिलाड़ी के फॉलोअर्स की संख्या विराट कोहली या रोहित शर्मा जैसी नहीं है। उनके लिए आवाज उठाने वाले ज्यादा लोग नहीं है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

गुजरात में ग्लोबल फिनटेक संचालन केंद्र स्थापित करेगा गूगल : पिचाई

वॉशिंगटन। बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल गुजरात स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक (गिफ्ट) सिटी में अपना वैश्विक फिनटेक संचालन केंद्र स्थापित करेगी। यह घोषणा गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद की। पिचाई ने यह भी कहा कि उनकी कंपनी 10 अरब अमेरिकी डॉलर के भारत डिजिटलीकरण कोष के माध्यम से भारत में निवेश करना जारी रखेगी। पिचाई ने कहा, ''हम गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना वैश्विक फिनटेक संचालन केंद्र खोलने की आज घोषणा कर रहे हैं। इससे भारत के फिनटेक नेतृत्व को मजबूती मिलेगी, जिसमें यूपीआई और आधार की अहम भूमिका है। हम उस नींव पर निर्माण करेंगे और इसे विश्व स्तर पर ले जाएंगे।''

भारत में 15 अरब डॉलर का और निवेश करेगी अमेजन

नईदिल्ली। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि कंपनी की योजना भारत में 15 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश करने की है, जिससे कंपनी का भारत में कुल निवेश 26 अरब डॉलर हो जाएगा। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने के बाद अमेजन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एंडी जैसी ने कहा कि कंपनी भारत में पहले से ही 11 अरब डॉलर का निवेश कर चुकी है। अमेजन भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। हमने अब तक 11 अरब डॉलर का निवेश किया है और 15 अरब डॉलर का और निवेश करने का इरादा है, जिससे कुल राशि 26 अरब डॉलर हो जाएगी। इसलिए हम साझेदारी के भविष्य को लेकर बहुत उत्सुक हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री ने अमेजन के अध्यक्ष और सीईओ के साथ सार्थक बैठक की।

80% प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भारत को होगा : अधिकारी

वॉशिंगटन। अमेरिकी रक्षा कंपनी जीई एयरोस्पेस-हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ हुए अपने समझौते के तहत एफ 414 लड़ाकू जेट इंजन के उत्पादन के लिए 80 प्रतिशत प्रौद्योगिकी भारत को हस्तांतरित करेगी। रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस ने भारतीय वायुसेना के लिए संयुक्त रूप से लड़ाकू जेट इंजन का उत्पादन करने के लिए बृहस्पतिवार को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका की मौजूदा राजकीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, इस समझौते के साथ, हमें जीई 414 इंजन बनाने में 80 प्रतिशत प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होगा, जो हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) एमकेआईआई के परिचालन प्रदर्शन को बढ़ाएगा।

गो फर्स्ट एयरलाइन को उड़ान भरने के लिए चाहिए 425 करोड़

नई दिल्ली। गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर शैलेंद्र अजमेरा ने एयरलाइंस फाइनेंसरों से अंतरिम वित्त में 425 करोड़ रुपये की मांग की है, ताकि एक पुनरुद्धार योजना बनाई जा सके और एयरलाइन का परिचालन फिर से शुरू करने में मदद मिल सके। बता दें कि गो फर्स्ट के दिवालिया मामले में शैलेंद्र अजमेरा को समाधान पेशेवर (आरपी) के रूप में नियुक्त किया गया है। संकट में फंसी विमानन कंपनी के कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) ने यह फैसला किया है। ऋणदाताओं ने उन्हें गो फर्स्ट के लिए आरपी (समाधान पेशवर) बनाने के लिए एनसीएलटी से मंजूरी ली है। सूत्रों ने हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भविष्य में विमानों के लिए दुरुस्त इंजनों की उपलब्धता और टिकट रद्द होने जैसी कुछ आकस्मिकताओं के आधार पर वित्तपोषण की जरूरत और बढ़ सकती है।

ऊंची विकास दर की आशा के बाद भी निराशा का माहौल क्यों?

अनिल तिवारी

पूर्व के सारे अनुमानों को पीछे धकेलते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.2% आंकी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष 8त्न की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है, हालांकि दो दिन पहले रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। खुदरा महंगाई दर पिछले 26 महीने के निचले स्तर 4.25 प्रतिशत पर आ गई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के मुताबिक औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर पिछले महीने के 1.6 प्रतिशत से बढ़कर 4.2% हो गई है। चालू महीने में रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह के साथ-साथ वित्त वर्ष 2023-24 के एक अप्रैल से 17 जून के बीच भारत के प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। प्रत्यक्ष कर संग्रह लगभग 12% की वृद्धि के साथ 3 लाख 79 हजार 760 करोड़ रूपया हो गया है। मौजूदा प्राइस के लिहाज से भारत की जीडीपी 3737 अरब डॉलर यानी 3.75 ट्रिलियन की हो गई है जोकि वर्ष 2014 में मात्र 2 ट्रिलियन की थी। कह सकते हैं कि आंकड़ों की नजर में भारतीय अर्थव्यवस्था की बल्ले-बल्ले है। लेकिन सरकार द्वारा ही जारी किए गए प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता के लगातार कम होने के आंकड़े तथा निर्माण क्षेत्र की सुस्ती के चिंताजनक धब्बे चांद की खूबसूरती वाले नहीं हैं बल्कि बेहतरीन बुर्के के पीछे छिपी झुर्रियों का दर्द उजागर करने वाले हैं।

वित्तीय वर्ष 2023 के जीडीपी के आंकड़े बता रहे हैं कि प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता मात्र 2.8% की दर से ही बढ़ी है, जो बहुत निराशाजनक है। प्रथम दृष्टया यह आंकड़ा इस बात को इंगित करता है कि कोरोना के बाद अब भी समाज का हर तबका आर्थिक

विकास की पटरी पर नहीं लौट पाया है। वहीं दूसरी तरफ 7.2% की विकास की दर और प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता के आंकड़े को साथ लेकर चलें तो यह तस्वीर इस बात को स्पष्ट कर देती है कि देश में आर्थिक-सामाजिक असमानता तेजी से बढ़ रही है। अमीरों की बढ़ी हुई क्रय क्षमता के कारण अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से अधिकाधिक बढ़ोतरी देखी गई है। होटल, पर्यटन, परिवहन और सेवा क्षेत्र के कुछ अन्य हिस्सों में दर्ज की गई बढ़ोतरी दरअसल अमीर तबके की बढ़ी हुई क्रय क्षमता का परिणाम है। दुरुह ब्याज नीति का असर निर्माण क्षेत्र पर पड़ा है। वर्ष 2023 में निर्माण क्षेत्र की विकास दर मात्र 1.3% हो गई है जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में यह 11त्न से अधिक थी। भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश में निर्माण की दर का गिरना चिंताजनक है।

भारत की ज्यादातर आबादी निम्न मध्यवर्गीय है और उसमें भी ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में महंगाई ऊंचे स्तर पर थी, जिसके चलते समाज का यह वर्ग बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ था। देश की प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता 2.8% मापी गई है, इसलिए वर्तमान की 7.2% की विकास दर भविष्य के अनुमानों के प्रति बहुत अधिक सकारात्मक रूप प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। पिछले वित्त वर्ष में अधिक महंगाई की दर को नियंत्रित करने के चक्कर में आरबीआई द्वारा एक लंबे अरसे के बाद ब्याज दरों को बहुत अधिक नियंत्रित किया गया जिसके अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। ज्ञात हो कि आठ विभिन्न क्षेत्र मिलकर अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर का निर्माण करते हैं, जिसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली शामिल है। इस कोर सेक्टर ने 7.6% की वृद्धि दर हासिल की है। समाज में आधारभूत ढांचे के विकास में कोयले के अलावा बिजली, स्टील और सीमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सबमें सबसे अधिक 15त्न की बढ़ोतरी कोयला के क्षेत्र में देखने को मिली है, बाकी बचे तीन सेक्टरों में भी 8त्न से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि आधारभूत संरचनाओं का विकास भारत में तेजी से हो रहा है।

मोदी ने दिया एजेंडा पत्रकारों के सवालों का जवाब

अजय सेठिया

भारत में विपक्षी दलों का हमेशा एक आरोप रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कांफ्रेंस नहीं करते, जिसमें पत्रकार उनसे सवाल पूछ सकें। वह जबसे प्रधानमंत्री बने हैं अपने मन की ही बात करते रहते हैं, जनता के मन की बात सुनते ही नहीं। उनका मानना है कि मीडिया उनसे जनता के मन की बात पर सवाल पूछना चाहता है, लेकिन वह मौक़ा नहीं देते। वह एकतरफा संवाद चला रहे हैं। बीच में इक्का दुक्का पत्रकार भी टीवी चैनलों की डिबेट में भाजपा प्रवक्ताओं से यही सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री मीडिया के कटघरे में खड़े क्यों नहीं होते। यह सच है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई प्रेस कांफ्रेंस नहीं की, लेकिन इसकी भी एक पृष्ठभूमि है। 2002 में जब गोधरा काण्ड हुआ, जिसमें 59 हिन्दुओं को ट्रेन के अंदर बंद करके ज़िंदा जला दिया गया था, तो उसकी प्रतिक्रिया में गुजरात में हिंसा हुई। उस हिंसा की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मीडिया ने एकतरफा रिपोर्टिंग की। उस रिपोर्टिंग का उद्देश्य तथ्य जनता के सामने रखना नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराना था। मीडिया का एक वर्ग पत्रकारिता का धर्म निभाने की बजाए, विपक्षी दल की भूमिका निभा रहा था। भाजपा विरोधी मीडिया के इस एक प्रभावशाली वर्ग से मिलीभगत करके विपक्षी दलों और वामपंथी प्रभाव वाले एनजीओ ने मोदी को देश और दुनिया में दंगाई के रूप में पेश किया। इसका प्रमाण यह है कि बाद में जब केंद्र में वामपंथियों के समर्थन से कांग्रेस की सरकार बनी, तो उन पत्रकारों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। वह रिपोर्टिंग कितनी एकतरफा थी, इसका एक प्रमाण यह है कि एकतरफा रिपोर्टिंग करने वाले एक पत्रकार ने बाद में सोहराबुद्दीन शेख की मुठभेड़ में मौत के सिलसिले में झूठी रिपोर्टिंग करने के लिए 2019 में कोर्ट से माफी माँगी। यह एक उदाहरण है कि उस समय पत्रकारों के एक वर्ग ने किस तरह तथ्यहीन और एकतरफा रिपोर्टिंग की थी। यह सच है कि उस समय की तथ्यहीन रिपोर्टिंग करने वालों में 99 प्रतिशत दिल्ली से गए पत्रकार थे। उन्होंने खुद को श्रेष्ठ मानते हुए स्थानीय पत्रकारों की तथ्यपरक रिपोर्टिंग को पूरी तरह से नकार दिया। पत्रकारिता के इस कुरूप चेहरे के कारण नरेंद्र मोदी के मन में एजेंडा पत्रकारों के प्रति नफरत का भाव होना स्वाभाविक है। जिसे दिल्ली के मीडिया ने 2014 के चुनावों में भी दोहराया, जब ज्यादातर पत्रकार पत्रकारिता करने के बजाए राजनीतिक प्रवक्ताओं की तरह व्यवहार कर रहे थे। लेकिन चुनाव में फैसला देश की जनता को करना था, न कि कुछ पत्रकारों को। जनता इस तरह की पत्रकारिता के बारे में क्या सोचती है, उसका जवाब जनता के 2014 के चुनाव में तो दिया ही, सितंबर 2014 में न्यूयार्क के मेडिसन स्क्वायर में भी दिया, जब एक पत्रकार को मोदी विरोधी टिप्पणी करने पर वहां उपस्थित स्थानीय लोगों ने बुरी तरह लताड़ा और वहां से जाने के लिए कहा। यह है मोदी की प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रेस कांफ्रेंस नहीं करने की पृष्ठभूमि। लेकिन जो सवाल मीडिया का एक वर्ग पूछना चाहता है, उसका नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले और बाद में भी कई बार जवाब दे चुके हैं। सवाल एक ही है कि उनके मुख्यमंत्री रहते और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके शासन में मुस्लिमों के साथ भेदभाव और उनका तथाकथित उत्पीड़न। बस यह एक ही सवाल है, जिसे मीडिया का वह वर्ग पूछना चाहता है, महंगाई, बेरोजगारी आदि तो हर प्रधानमंत्री से स्थाई सवाल होते हैं। मुस्लिम उत्पीड़न के बारे में जो सवाल मीडिया का वह एक वर्ग पूछना चाहता है, उसे विपक्ष एक नहीं अनेक बार संसद में उठा चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद में दिए गए अपने भाषणों में विपक्ष के इन आरोपों का जवाब दे चुके हैं। ये सभी आरोप उसी एजेंडा और दुर्भावना से प्रेरित हैं, जो दुर्भावना 2002 में भी थी, इनमें तथ्यात्मक कुछ भी नहीं है। मीडिया के इसी वर्ग ने पिछले कुछ सालों में मुस्लिम उत्पीड़न के मनगढ़ंत आरोप को मानवाधिकार का मुल्लमा चढ़ा कर अन्तरराष्ट्रीय बाज़ार में बेचा है। पिछले कुछ समय से मुस्लिम उत्पीड़न के साथ दलितों को भी जोड़ दिया गया है, ताकि खबरों के अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में मानवाधिकार हनन की थ्योरी को आसानी से बेचा जा सके।

एनडीए कमजोर स्थिति में आ गया

रमेश सर्राफ धमोरा

कहने को तो केंद्र में भाजपा नीत एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। मगर सरकार में शामिल दलों की सूची देखें तो एनडीए के नाम पर इक्का-दुक्का छोटे दलों को छोड़कर कोई भी बड़ी पार्टी केंद्र सरकार में शामिल नहीं है। कभी देश के अधिकांश बड़े दल एनडीए का हिस्सा होते थे। मगर आज स्थिति उसके उलट हो गई है। अब एनडीए नाम मात्र का रह गया है। 1998 में कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस विरोधी राजनीतिक दलों को एक छतरी के नीचे लाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का गठन किया था। जॉर्ज फर्नांडिस को इसका संयोजक बनाया गया था। 1998 के लोकसभा चुनाव से पूर्व गठित एनडीए में शामिल 16 दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बना ली थी। जो मात्र एक साल बाद ही अन्नाद्रमुक के समर्थन वापस लेने से गिर गई थी। 1999 में फिर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी जो 2004 तक चली थी। गठन के समय एनडीए में छोटे-बड़े कुल 16 राजनीतिक दल शामिल थे। 1999 के चुनाव में 21 दल, 2004 में 12 दल, 2009 में 8 दल, 2014 में 23 दल व 2019 में 20 राजनीतिक दल एनडीए में शामिल होकर एक साथ चुनाव लड़े थे।

मगर अब एनडीए की स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। एनडीए में शामिल अधिकांश बड़े राजनीतिक दल भाजपा से गठबंधन तोड़ कर अलग हो गए हैं। वर्तमान समय में एनडीए में छोटे बड़े मिलाकर कुल 13 राजनीतिक दल शामिल हैं। जसिमें भी बहुत-सी पार्टियां नाम मात्र की ही हैं। एनडीए के कुनबे की बात करें तो इसमें भाजपा के अलावा अपना दल (सोनेलाल), ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट, नागा पीपुल्स फ्रंट, लोक जनशक्ति पार्टी, शिवसेना (शिंदे), सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस, अन्नाद्रमुक, पीएमके, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) जैसी पार्टियां शामिल हैं।

2019 के लोकसभा चुनाव के बाद शिरोमणि अकाली दल, जनता दल (यूनाइटेड), शिवसेना, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जैसे कई दलों ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। एनडीए छोड़ने वाले सभी दलों ने भाजपा नेतृत्व पर आरोप लगाया कि वह अपनी मनमानी करता है। एनडीए गठबंधन नाम मात्र का रह गया है। सारे फैसले भाजपा नेतृत्व ही करता है। 2019 में शिवसेना ने एनडीए में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। मगर बाद में राज्य विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के पद को लेकर विवाद होने के बाद शिवसेना ने एनडीए छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में महा विकास आघाडी बनाकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बना ली। हालांकि भाजपा ने शिवसेना में ही फूट डलवा कर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनवा दिया। इसी तरह बिहार में मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी के तीनों विधायकों को तोड़कर भाजपा में विलय करा लिया। उत्तर प्रदेश में भी ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए से बाहर निकल गई थी।

कभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की द्रुमक, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, तेलुगू देशम पार्टी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की जनता दल (सेकुलर), तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की तेलंगाना राष्ट्र समिति, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, हरियाणा जनहित कांग्रेस, तमिलनाडु की डीएमडीके, पीएमके, महाराष्ट्र का स्वाभिमानी पक्ष, बिहार में जीतन राम मांझी की हम पार्टी एनडीए का हिस्सा थी। आज ये सभी पार्टियां भाजपा से दूर जा चुकी हैं।

शिरोमणि अकाली दल और राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने तो किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों से खफा होकर एनडीए को छोड़ा था। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्री का पद भी छोड़ दिया था। उसके बाद पंजाब में हुए विधानसभा के चुनाव में भी भाजपा व शिरोमणि अकाली दल ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था। 2019 में राजस्थान की नागौर सीट हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को देकर भाजपा ने उससे समझौता किया था। मगर अब हनुमान बेनीवाल भी अपनी एकला चलो की नीति पर काम कर रहे हैं। वह राजस्थान में खुलकर भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं और भाजपा को उखाड़ने में लगे हैं। वर्तमान में देश के दस प्रदेशों में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं व 5 प्रदेशों में भाजपा नीत गठबंधन के मुख्यमंत्री शासन कर रहे हैं। वहीं देश के चार प्रदेशों में कांग्रेस व 3 प्रदेशों में कांग्रेस यूपीए गठबंधन के मुख्यमंत्री शासन कर रहे हैं।

अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। वहीं सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेम सिंह तमांग, नागालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेफ्यू रियो, मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी के कानराड संगमा, महाराष्ट्र में शिवसेना (शिंदे) गुट के एकनाथ शिंदे, पुडुचेरी में अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री हैं।

पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को हरियाणा में बहुमत नहीं मिलने पर वहां जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला को उपमुख्यमंत्री तथा कुछ निर्दलीय विधायकों को मंत्री बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में अपना दल व निषाद पार्टी के विधायक भी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। असम में असम गण परिषद व यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल सरकार में शामिल है। गोवा में भाजपा को पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था इस कारण वहां महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी व निर्दलीयों के सहारे से भाजपा की सरकार चल रही है। त्रिपुरा में इंडिजिनियस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा का एकमात्र विधायक शुक्ला चरण नोएतिया भी सरकार में शामिल है।

कभी कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, बालासाहेब ठाकरे, जॉर्ज फर्नांडीस, शरद यादव, नवीन पटनायक, चंद्रबाबू नायडू, जे. जयललिता, प्रकाश सिंह बादल, शिबू सोरेन, ममता बनर्जी और प्रमोद महाजन जैसे दिग्गज नेताओं ने एनडीए का गठन किया था। उनका यह प्रयोग सार्थक भी साबित हुआ था। गठन के कुछ समय बाद ही एनडीए की केंद्र में सरकार भी बन गयी थी। बाद में एनडीए की सरकार को हटाने के लिए ही कांग्रेस ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस (यूपीए) का गठन किया था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दस वर्षों तक यूपीए-एक और यूपीए-दो कि सरकार चलायी थी।

भाजपा जैसे-जैसे मजबूत हो रही है वैसे-वैसे ही एनडीए गठबंधन कमजोर होता जा रहा है। भाजपा अपने अधिकांश पुराने साथियों की एनडीए से विदाई कर चुकी हैं। मगर 2024 के लोकसभा चुनाव में संघर्ष कड़ा होता देख भाजपा को फिर से एनडीए के साथियों की याद आने लगी है। इसीलिये भाजपा फिर अपने पुराने साथियों को एनडीए में लाने का प्रयास कर रही है। लेकिन भाजपा की फितरत से वाफिक दल शायद ही फिर एनडीए में लौटें। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

गोपालपूर्वतापिन्युपनिषद् (भाग-6)

गतांक से आगे...

तृतीय गोविन्दाय पद से कामधेनु गौ और वेदादि विद्याओं को प्रकट किया। उसके पश्चात् चतुर्थ पद गोपीजनवल्लभाय से स्त्री-पुरुषादि की संरचना की और सबसे बाद में पञ्चम पद स्वाहा से सम्पूर्ण जड़- चेतनमय चर-अचर विश्व को प्रादुर्भूत किया। [यहाँ जिस अष्टादशार्ण (अष्टदशाक्षर मंत्र की विवेचना की है, वह मन्त्र इस प्रकार है- क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा।] प्राचीनकाल में राजर्षि चन्द्रध्वज मोहरहित होकर भगवान् श्रीकृष्ण के पूजन एवं कार द्वारा सम्पुटित अष्टादशाक्षर मंत्र के जप एवं ध्यान के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करके सङ्गरहित हो गये। भगवान् विष्णु (श्रीकृष्ण) के उस अविनाशी परमधाम गोलोक का ज्ञानी और प्रेमी भक्तजन निरन्तर दर्शन करते रहते हैं।

आकाश में सूर्य के सदृश वे (भगवान) परम व्योम में चतुर्दिक् संव्याप्त एवं प्रकाशस्वरूप विद्यमान हैं। (उस शाश्वत परम अविनाशी गोलोक धाम की प्राप्ति, पूर्व में कहे हुए अष्टादशाक्षर मन्त्र के जप एवं ध्यान से ही सम्भव होती है, अत: इस दिव्य मन्त्र का प्रतिदिन ही जप करना चाहिए। (उपर्युक्त अष्टादशाक्षर मंत्र के सन्दर्भ में) कुछ मुनिगण ऐसा कहते हैं कि जिसके प्रथम पद (क्लीं) से पृथ्वीतत्त्व, द्वितीय पद (कृष्णाय) से जल तत्त्व, तृतीय पद (गोविन्दाय) से तेजस् (अग्नितत्त्व), चतुर्थ पद (गोपीजनवल्लभाय) से वायुतत्त्व और अन्तिम पञ्चम पद (स्वाहा) से आकाश तत्त्व का प्राकट्य हुआ; वह पञ्चमहाव्याहृतियों से युक्त अष्टादशाक्षर वैष्णव मन्त्र श्रीकृष्ण के स्वरूप को तेजोमय बनाने वाला है। उस मन्त्र का मोक्ष प्राप्ति के लिए सतत जप एवं ध्यान करते रहना चाहिए।

इस सन्दर्भ में यहाँ पर यह गाथा प्रसिद्ध है जिस (अष्टादशाक्षर) मंत्र के प्रथम पद से पृथ्वी उत्पन्न हुई, द्वितीय पद से जलतत्त्व का आविर्भाव हुआ, तृतीय पद से तेजस् (अग्नि) का प्राकट्य हुआ, चतुर्थ पद से वायु तत्त्व प्रकट हुआ और पंचम पद से आकाश तत्त्व का प्रादुर्भाव हुआ, उस एकमात्र अष्टादशाक्षर मन्त्र का ही सर्वदा जप एवं ध्यान करना चाहिए। उस मन्त्र के जप द्वारा ही राजर्षि चन्द्रध्वज ने श्रीकृष्ण के अविनाशी शाश्वत गोलोक धाम को प्राप्त किया। वह गोलोक धाम परम पवित्र, विमल, शोक-विहीन, लोभ आदि से रहित, समस्त प्रकार की आसक्ति से रहित है। वह ऊपर कहे पाँच पदों वाले मन्त्र से भिन्न नहीं है।

क्रमश:...

अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस

ललित गर्ग

अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य एवं नशा निरोधक दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जून को समूची दुनिया में मनाया जाता है। नशीली वस्तुओं और पदार्थों के कहर एवं प्रकोप से मुक्ति हेतु 'संयुक्त राष्ट्र महासभा' ने 7 दिसम्बर, 1987 को इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया था। यह एक तरफ लोगों में नशामुक्ति की चेतना जगाता है, वहीं दूसरी ओर नशे के लती लोगों के उपचार की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण कार्य करता है। देश एवं दुनिया में दिन-प्रतिदिन शराब, मादक पदार्थों व द्रव्यों के सेवन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक जन-अभियान रूप में यह दिवस मनाया जाता है। समाज में बढ़ती हुई मद्यपान, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट की लत एवं नशीले मादक द्रव्यों, पदार्थों के दुष्परिणामों के कारण अनेक जिन्दगियां आज मौत की अंधी सुरंगों में धंस रही है।

विश्व की गम्भीर समस्याओं में प्रमुख है नशीले पदार्थों का उत्पादन, तस्करी और सेवन की निरंतर हो रही वृद्धि। नई पीढ़ी इस जाल में बुरी तरह कैद हो चुकी है। आज हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी नशे का आदी हो चुका है। नशीले पदार्थों के छोटे-छोटे पाउचों से लेकर तेज मादक पदार्थों, औषधियों तक की सहज उपलब्धता इस आदत को बढ़ाने का प्रमुख कारण है। इस दीवानगी को ओढ़ने के लिए प्रचार माध्यमों ने भी भटकाया है।

सरकार भी विवेक से काम नहीं ले रही है। कोरोना महासंकट के लॉकडाउन के दौरान हमने सरकारों की छटपटाहट शराब की दुकानों को खोलने को लेकर देखी। सरकार की आर्थिक आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है नशे का उत्पाद एवं व्यापक स्तर पर इंसानों की धमनियों तक इसे पहुंचाना। वे शराबबन्दी का नारा देती है, नशे की बुराइयों से लोगों को आगाह भी करती है और शराब, तम्बाकू का उत्पादन भी बढ़ा रही है। राजस्व प्राप्ति के लिए जनता की जिन्दगी से खेलना क्या किसी लोककल्याणकारी सरकार का काम होना चाहिए?

यह सर्वविदित है कि नशे की संस्कृति युवा पीढ़ी को गुमराह कर रही है। अगर यही प्रवृत्ति रही तो सरकार, सेना और समाज के ऊंचे पदों के लिए शरीर और दिमाग से स्वस्थ व्यक्ति नहीं मिलेंगे। एक नशेड़ी पीढ़ी का देश कैसे अपना पूर्व गौरव प्राप्त कर सकेगा? प्रसिद्ध फुटबाल खिलाड़ी मैराडोना, पॉप संगीत गायक एल्विस प्रिंसले, तेज धावक बेन जॉनसन, युवकों का चहेता गायक माइकल जैक्सन, ऐसे कितने ही खिलाड़ी, गायक, सिने कलाकार नशे की आदत से या तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं या बरबाद हो चुके हैं। नशे की यह जमीन कितने-कितने आसमान खा गई। विश्वस्तर की ये प्रतिभाएं नशे की लत के कारण कीर्तिमान तो स्थापित किए हैं, पर नई पीढ़ी के लिए स्वस्थ विरासत नहीं छोड़ पाई हैं। नशे की ओर बढ़ रही युवापीढ़ी बौद्धिक रूप से दरिद्र बन रही है। जीवन का माप सफलता नहीं सार्थकता होती है। सफलता तो गलत तरीकों से भी प्राप्त की जा सकती है। जिनको शरीर की ताकत खैरात में मिली हो वे जीवन की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं?

टिकाऊ दोस्ती की ओर बढ़े अमेरिका और भारत

स्वर्ण सिंह

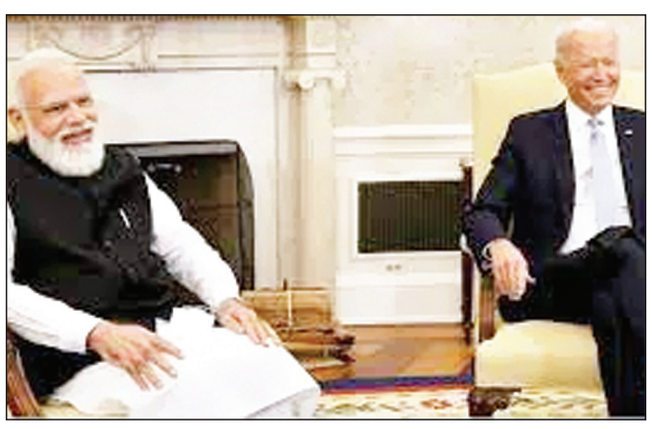

विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों- अमेरिका और भारत की बढ़ती हिस्सेदारी के लिए अब 'आकाश भी सीमा नहीं है।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश उनकी इस यात्रा की सटीक समीक्षा करता है। राष्ट्रपति बाइडन ने भी कहा कि अमेरिका और भारत के आपसी रिश्ते 'इतिहास में इतने सुदृढ़, गतिशील और करीबी कभी नहीं थे, जितने आज हैं।' इससे पहले, 4 फरवरी 2022 को पेइचिंग में जारी किए गए चीन और रूस के राष्ट्रपतियों- शी चिनफिंग और व्लादिमीर पूतिन के साझा बयान में भी कुछ इसी तरह से 'कोई सीमा नहीं' वाली दोस्ती का जिक्र हुआ था। रूस-चीन के उस गठबंधन से दूसरे शीतयुद्ध की अटकलें भी लगने लगी थीं। तब से यूक्रेन युद्ध के चलते रूस की चीन पर बढ़ती निर्भरता, भारत में रूस के हथियारों का स्रोत बने रहने की मंशा और हैसियत पर बढ़ती चिंता और भारत-चीन के बीच तीन साल से सीमा पर चल रहे टकराव से अमेरिका की भारत को अपने साथ जोड़ने की कोशिशें और भी मजबूत हुई हैं।

दूरगामी है नजरिया

पर क्या केवल चीन और रूस की सामरिक और भू-राजनीतिक चुनौतियों से अपने वैश्विक नेतृत्व को बचाने की मंशा से ही अमेरिका भारत को लुभा रहा है? भारत में आज निश्चयात्मक विदेश नीति का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यूक्रेन युद्ध में भारत की सक्रिय तटस्थता इसका सटीक उदाहरण है। इसके बावजूद अमेरिका भारत से दोस्ती बढ़ाना चाहता है। पिछले दो दशकों में भारत के रक्षा उपकरणों के आयात में भी बदलाव आया है। इसमें रूस का हिस्सा 68 प्रतिशत से घट कर केवल 47 प्रतिशत रह गया है। आज भारत के रक्षा उपकरणों के आयात में फ्रांस दूसरा बड़ा स्रोत है। पिछले साल इसका भारत के कुल आयात में हिस्सा 29 फीसदी तक था, जबकि अमेरिका का केवल 11 प्रतिशत था।

आज चीन और रूस को छोड़कर सारी बड़ी शक्तियां अमेरिका की दोस्त या अलायंस पार्टनर हैं। उसी तरह वह उभरते हुए भारत को भी अपना दोस्त या अलायंस पार्टनर बनाना चाहता है। पर ऐसा अमेरिका अपनी दीर्घकालिक शांति और समृद्धि के लिए कर रहा है। क्योंकि चीन और रूस की चुनौतियां सुलझ भी जाएं तो आतंकवाद, सर्वव्यापी महामारियां, पर्यावरण जैसी दर्जनों दूसरी चुनौतियां अमेरिका के सामने बनी रहेंगी, जिनको सुलझाने में भारत अहम योगदान कर सकता है।

भारत को भी अपने विकास और सुरक्षा के लिए अमेरिका की दोस्ती फायदेमंद लगती है। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि दर वाला भारत, जो आज दुनिया में पांचवें स्थान पर है, और पांच से आठ वर्षों में तीसरे स्थान पर होगा, सभी विकसित देशों से हिस्सेदारी बना रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने अमेरिकी संसद को याद दिलाया, 2016 से ही भारत अमेरिका से संबंध प्रगाढ़ करने में अपने 'ऐतिहासिक संकोच' से बाहर आ चुका था। प्रधानमंत्री मोदी के इस राजकीय दौरे में दोनों ओर से दिखी असाधारण गर्मजोशी इस बात का संकेत है कि ये रिश्ते 21वीं शताब्दी की अंतरराष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित कर सकते हैं।

शायद यही कारण है कि इस यात्रा में भारत का पूरा ध्यान तकनीक हस्तांतरण पर रहा। जैसा कि भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य में कहा गया, तकनीक में हिस्सेदारी ही इनके आपसी रिश्तों को परिभाषित करेगी। परंतु इसमें रक्षा के साथ-साथ और भी सभी तरह की अतिआधुनिक तकनीक में साझेदारी को आगे बढ़ाने की बात कही गई। अभी तक लिए गए निर्णयों में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण, उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के विज्ञान और तकनीक में हिस्सेदारी के साथ-साथ दूसरे तकनीक के क्षेत्र जैसे क्वांटम, सेमिकंडक्टर, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस में भी आदान-प्रदान के विशिष्ट तंत्रों और मंचों की घोषणा की गई।

प्रधानमंत्री की इस राजकीय यात्रा में दोनों देशों ने कई वर्षों से चल रहे अपने पांच खरब डॉलर के लक्ष्य को एक बार फिर से दोहराया है। आज के बदलते हुए रिश्तों के संदर्भ में पांच खरब का लक्ष्य संभव लगता है। इसके लिए दोनों तरफ से कोशिशें भी हो रही हैं। दोनों देशों ने अपने विश्व व्यापार संगठन में विवाद निपटाने के तंत्र में चल रहे छह मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया। हाल के वर्षों में अपने आपसी आयात पर बढ़ाए गए सीमा शुल्क भी हटाने का निर्णय किया गया। ज्ञान और कौशल के आदान-प्रदान को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका बेंगलुरु और अहमदाबाद में और भारत सीऐटल शहर में नए वाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है। इससे अमेरिका जाने वाले भारतीयों को वीजा और जानकारी पाने में आसानी होगी। पिछले साल अमेरिका में 'एच-1 बी' वीजा पर आए करीब 4.5 लाख विदेशी कर्मियों में 73 फीसदी भारतीय थे। इस वीजा की तीन साल की अवधि समाप्त होने पर भारतीय नागरिकों को इसके नवीनीकरण के लिए भारत लौटकर सारी प्रक्रिया दोहरानी पड़ती थी। यह प्रक्रिया अब वे अमेरिका में रहकर ही कर पाएंगे।

ज्यादा जोर रक्षा पर

फिर भी ज्यादा जोर भारत-अमेरिका की उभरती हुई संयुक्त रक्षा-उत्पादन की हिस्सेदारी पर बना रहा। हालांकि रक्षा क्षेत्र में भी भारत-अमेरिका की उभरती हुई साझेदारी हथियारों तक सीमित नहीं है। इसमें विश्वविद्यालयों, स्टार्ट-अप्स, थिंक टैंक्स और अन्य संस्थानों के तकनीक के मौलिक नवाचार और वैज्ञानिक विकास के लिए सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। यह सब इसलिए क्योंकि आज का भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने की कोशिश में है। भारत ने 2020 के 'आर्टेमिस समझौते' पर भी हस्ताक्षर किए। यह सन 1967 की अंतरिक्ष संधि पर आधारित, अमेरिका द्वारा बनाई गई एक गैर-बाध्यकारी व्यवस्था है जो अंतरिक्ष में असैनिक शोध के मौलिक आदर्श व्यवहार के मापदंडों को रेखांकित करती है। इसमें अभी तक 22 देश जुड़ चुके हैं। यह अमेरिका का भरोसा जीतने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और भविष्य में तकनीकी नवाचार में साझेदारी की नींव और सुदृढ़ करेगा।

बापू की दिनचर्या

समाचारपत्रावलोकन

साधारणत: मध्याह्न में भोजन से निवृत्त होकर विश्राम करने तथा एक झपकी लेने से पहले देशी तथा विदेशी पत्रों के चुने समाचार बापू स्वयं पढ़ा करते। दक्षिण अफ्रीका से भारत तक, जहाँ भी उन्होंने सार्वजनिक कार्य किए, उनकी कार्य-प्रणाली में पत्रकारिता का विशेष योगदान रहा। वह उनकी दिनचर्या में आबद्ध थी। अफ्रीका में रहते हुए इंडियन ओपीनियन तथा भारत में यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और हरिजनसेवक जैसे समाचारपत्रों का संपादन समाचार-पठन और श्रवण से संबद्ध था। बापू आरंभ से नियमपूर्वक बांबे क्रानिकल तथा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते। सेवाग्राम-निवास के पश्चात् वे नागपुर टाइम्स पर भी एक दृष्टि डाल लिया करते। श्री नटराजन के साप्ताहिक इंडिया सोशल वेलफेयर के अग्रलेख तथा रामानंद चटर्जी के माडर्न रिव्यू की टिप्पणियों का वे अवश्य अवलोकन करते। पाकिस्तानी पत्र डान तथा भारतीय साम्यवादी दल के साप्ताहिक जनयुग की कतरनें भी वे बराबर देखते। डॉन को वे विशेष रूप से पढ़ते या सुनते। पत्रकारिता बापू के लिए लोकहित तथा लोकसेवा का व्रत था। वह जीवन-कार्य अग्रसर करनेवाला सहायक साधन थी, जीविका का साधन नहीं। इस विषय में उनके कुछ आदर्श थे। उनमें सत्य प्रमुख था। उन्होंने अनेक पत्र सफलतापूर्वक चलाए, वर्षों कठोर कारावास भोगा और वे समर्थ एवं निर्भीक पत्रकार स्वीकारे गए। उनके महत्त्वपूर्ण लेखों को वाइसराय। दूरभाष (टेलीफोन) पर सुना करते। वे और उनके अखबार सत्य के विषय में प्रमाण माने जाते। इतना होने पर भी उनके सान्निध्य में हर व्यक्ति का मान सुरक्षित रहता। यदि उन्हें महसूस हो जाता कि उनसे भूल हुई है तो वे निस्संकोच क्षमायाचना करने में हिचकते नहीं, किंतु उनसे जबर्दस्ती क्षमायाचना कराना सर्वथा असंभव था। पत्रकारिता में द्विअर्थी भाषा का प्रयोग तथा लेखनी की निरंकुशता के बापू परम विरोधी थे। द्विअर्थी भाषा को वे सज्जनों और मर्दों की भाषा नहीं मानते और लेखनी के निरंकुश प्रवाह से सर्वनाश संभव बताते। प्राप्त सारी जानकारी प्रकाशित करने के वे विपक्ष में थे। लोक हित तथा सेवा के अपने आदर्श के अनुरूप वे उतनी ही जानकारी प्रकाश में लाने के पक्ष में थे, जितनी आवश्यक होती है। आरंभ में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपीनियन में विज्ञापन लिए जाते।

क्रमश: ...

संक्षिप्त समाचार

सीएम भूपेश की घोषणा के बाद कुंडा में खुलेगा कॉलेज, इसी सत्र से पढ़ाई होगी

कवर्धा। जिले के पंडरिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम कुण्डा के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। इसी वर्ष से ही महाविद्यालय संचालित होने जा रहा है।इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा के बाद प्रशासन कॉलेज संचालन करने की तैयारी शुरु कर दी है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में किया था वादा-छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पंडरिया विधानसभा के ग्राम कुकदूर पहुंचे थे। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों की मांग पर स्थानीय विधायक ममता चंद्राकर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ग्राम कुण्डा में कॉलेज खोलने की मांग की थी। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को आश्वासन देकर गए थे। अब मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है।इसी सत्र से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है। गरीब परिवारों को मिलेगा बड़ा सहारा-कुंडा में मैट्रिक पास करने के बाद छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय की शिक्षा लेने के लिए 20 किलोमीटर दूर ब्लॉक मुख्यालय पंडरिया जाना पड़ता था।या फिर 45 किलोमीटर जिला मुख्यालय में रह कर महाविद्यालय की शिक्षा हासिल करते थे।क्षेत्र के गरीब परिवार के बच्चे गरीबी के कारण बस का किराया और खर्च निर्वहन नहीं कर पाते थे । जिसकी वजह से महाविद्यालय की शिक्षा हासिल नहीं होती थी। नौकरी की उम्मीद छोड़कर आगे परिवार चलाने खेती किसानी या मजदूरी कार्य करने जुट जाते थे।

लालू यादव की सलाह मानें राहुल तो हमें भी मिठाई खाने को मिले : बृजमोहन

रायपुर। पटना में शुक्रवार को देश के विपक्षी दलों की मीटिंग हुई। इसमें शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दी। इस पर प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने चुटकी ली। उन्होंने कहा अगर राहुल गांधी जी ,लालू यादव की बात मानते हैं तो खुशी कि बात है हमें भी मिठाई खाने का अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ में जो घोटाले-घपले हुए हैं, सभी का सूबत केन्द्र सरकार के पास है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस चला चली की बेला में है। उनमें एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है। अन्य दलों के साथ संयुक्त बैठक से कुछ नहीं होने वाला।

एआईसीसी सचिव व छत्तीसगढ़ प्रभारी सप्तगिरी आज आएंगे

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का रविवार को दोपहर 12 बजे कोरापुट से जगदलपुर पहुंचेगे। जगदलपुर सर्किट हाउस में वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। दोपहर 1.40 बजे जगदलपुर से रायपुर के लिये रवाना होंगे। रात्रि विश्राम रायपुर में करेंगे। उल्का 26 जून को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित बस्तर संभाग में बूथ चलो अभियान में शामिल होंगे। रात्रि विश्राम जगदलपुर सर्किट हाउस में करेंगे। 27 जून मंगलवार को सुबह 11 बजे जगदलपुर से कोरापुट के लिये रवाना होंगे।

भूपेश ने अपने पोते का कराया आधार पंजीयन, योजना का लिया लाभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मितान योजना की प्रदेश के सभी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। इस योजना की चर्चा पूरे देश-प्रदेश में है। इसी क्रम में सीएम भूपेश बघेल ने भी अपनी सरकार की इस योजना का लाभ लिया है। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने पोते का मितान योजना से आधार पंजीयन कराया है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट इस आशय की जानकारी दी। सीएम बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि आप सबकी तरह ही आज मेरे भी घर 'मितान' ने पहुंचकर मेरे पौत्र का आधार पंजीयन किया है। अब सिर्फ़ एक कॉल पर इतनी सुविधाएं मिलने पर सबको सुगमता हो रही है, यह देखकर संतोष है। मितान योजना का लाभ पाने के लिए 14545 पर कॉल करें। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने मितान योजना की घोषणा की थी। इससे पहले ये योजना केवल 14 नगर निगमों में ही लागू थी। फिलहाल, मितान योजना का लाभ प्रदेश के सभी 44 नगर पालिकाओं में मिल रहा है।

राइस मिल में लगी भीषण आग लाखों का हुआ नुकसान

तिल्दा नेवरा। रायपुर से लगे तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र के कालेज रोड स्थित रानू गाँधी राइस मिल में बीती रात भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पांच से छह घंटे में आग पर काबू पाया। इस आगजनी में राइस मिलर को लाखों का नुकसान होना बताया जा रहा है।

स्टेट पॉवर कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर की चयनित सूची जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी ने डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। इसमें पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव क्षेत्र के 238 पदों के लिए एवं ट्रांसमिशन कंपनी के 50 पदों के लिये अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं। यह सूची पॉवर कंपनी की वेबसाइट में अपलोड की गई है। अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिये पॉवर कंपनी की वेबसाइट सीएसपीसी डॉट को डॉट इन का अवलोकन कर सकते हैं।

रायपुर में बनेगा सिकल सेल का विश्वस्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रखी आधारशिला, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का फायदा पड़ोसी राज्यों के मरीजों को भी मिलेगा

■ **निःशुल्क जांच और इलाज के साथ सिकलसेल पर होगा शोध**

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर के देवेन्द्र नगर चौक जेल रोड में सिकल सेल संस्थान के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भूमिपूजन किया। इस संस्थान का 2.96 एकड़ भूमि में किया जाएगा, जिसमें 48 करोड़ 12 लाख रूपए की लागत आएगी। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होगी। यह पहल न केवल प्रदेश के लोगों के लिए, बल्कि सीमावर्ती राज्यों के लिए भी लाभप्रद होगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले साढ़े चार साल में स्वास्थ्य विभाग में अभूतपूर्व कार्य हुए। स्वास्थ्य जांच के लिए हाट बाजार व शहर में अन्य माध्यम से लोगों को सुविधाएं मिली है। मलेरिया मुक्त बस्तर आभियान तथा बाद में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चलाया गया जिससे मलेरिया में 65 प्रतिशत तक की कमी आई है। सिकलसेल से छत्तीसगढ़ की आबादी के लगभग 10 प्रतिशत लोग ग्रसित हैं। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसीलिए यह बड़ी चुनौती भी है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ लगातार काम कर रही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में राज्य के सिकलसेल संस्थान का उन्नयन होगा, इससे सुविधाएं बढ़ेगी, शोध कार्यों में तेजी आएगी। सिकलसेल की रोकथाम के लिए इलाज के साथ-साथ जागरूकता भी जरूरी है। यदि रोगी का समय पर सही उपचार शुरू कर दिया जाए, समय पर उन्हें दवाइयां उपलब्ध करा दी जाएं, तो उनके शारीरिक दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। वे भी लम्बी आयु का जीवन जी सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि समय पर रोग की पहचान कर ली जाए। सिकलसेल के अनुवांशिक गुण वाले व्यक्तियों की पहचान से पूर्व करके उन्हें आवश्यक परामर्श दिया जा सकता है, ताकि इस रोग के प्रसार को भी कम किया जा सके।

वर्तमान में सिकलसेल संस्थान द्वारा सिकलसेल मरीजों को जांच, परामर्श, उपचार एवं दवाईयों की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। अक्टूबर 2022 से प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों और शासकीय मेडिकल कॉलेजों में सिकलसेल जांच एवं परामर्श केंद्रों की शुरुआत की जा चुकी है। अब इसे निचले स्तर पर भी विस्तारित किया जा रहा है। विकासखण्ड स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच एवं परामर्श केंद्रों की स्थापना का काम शुरू हो चुका है। इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। ग्रामीण स्तर पर मितानीनों के माध्यम से सिकलसेल मरीजों की पहचान की जाएगी और फिर उन्हें उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा, पूर्व सांसद श्री नंदकुमार साय पद्मश्री डॉ. ए.टी.के. दाबके, सिकल सेल महानिदेशक डॉ. उषा जोशी, डीन डॉ. तृप्ति नागरिया, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद कैसर अब्दुल हक उपस्थित थे। स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि 2.96 एकड़ भूमि में सिकल सेल संस्थान छ.ग. रायपुर का उन्नयन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में किया जा रहा है। जिसका निर्माण 48 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जिसमें आने वाले समय में मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता होगी। 100 बेड की सुविधा होगी। जिसमें आपात् चिकित्सा, ओटी, आईसीयू, ओपीडी, पुरुष वार्ड व महिला वार्ड तथा किड्स वार्ड का निर्माण किया जा रहा है। संस्थान में एक रिसर्च लैब बिल्डिंग भी होगा, जिसमें जेनेटिक लेवल रिसर्च हेतु विभिन्न प्रकार के लैब होंगे,जिससे इस बीमारी के इलाज से संबंधित शोध कार्य किया जा सकेगा।

संस्थान में 250 व्यक्तियों की क्षमता का एक ऑडिटोरियम और रिक्रिएशनल ब्लॉक का भी निर्माण किया जा रहा है, ताकि सिकल सेल से पीड़ित बच्चों का मनोरंजन किया जा सके। इसी भवन में कैंटीन का निर्माण किया जा रहा है, ताकि दूर-दराज से मरीज के साथ आए हुए परिजन कैंटीन से भोजन प्राप्त कर सके। इसके अलावा संस्थान में एक प्रशिक्षण ब्लॉक का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सिकल सेल से संबंधित स्टॉफ के लिए ट्रेनिंग सेंटर, क्लास रूम व रुकने की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। नवीन भवन परिसर में डॉक्टर्स के लिए 24 फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है, ताकि 24 घंटे डॉक्टर की उपलब्धता बनी रहे।

पंचायत चुनाव : गृहमंत्री साहू ने प्रत्याशी लक्ष्मी साहू के लिए जनता से माँगा आशीर्वाद

■ **जन हितकारी नीतियों के दम पर गढ़ रहे हैं नवा छत्तीसगढ़ - ताम्रध्वज**

दुर्ग। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में क्षेत्रीय विधायक व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी लक्ष्मी साहू के पक्ष में जनसंपर्क कर जनता से उन्हें भरी मतों से विजयी बनाने की अपील की।

उन्होंने ग्राम कोटनी, नगपुरा, बोरई, दमोदा, खुर्शीडीह, खुरशुल, गनियारी,और पीपरछेड़ी में जनसंपर्क कर छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं एवं नीतियों के बारे में बताते हुए एवं उनसे मिले लाभ के संबंध में चर्चा कर क्षेत्र के विकास के लिए जनता से कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी लक्ष्मी साहू को अपना आशीर्वाद प्रदान करने का निवेदन किया। उन्होंने आगे कहा कि स्व. शालानी यादव के निधन के बाद यंहा उपचुनाव हो रहा है; आप सभी ने अपील है कि अपना आशीर्वाद प्रदान कर लक्ष्मी साहू को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएं, वही स्व.शालनी यादव को एक सच्ची श्रद्धांजली होगी।

ताम्रध्वज ने अपने सम्बोधन में कहा कि आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों का कर्जा माफ, राजीव गांधी किसान योजना, 2500 रूपये में धान खरीदी, बेरोजगारी भत्ता,गोधन न्याय योजना सहित शिक्षा व स्वास्थ्य में भी क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं, जिससे प्रदेश के हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर प्रदेश के किसानों, मजदूरों, युवाओं एवं महिलाओं की उन्नति करने और नवा छत्तीसगढ़ गढने संकल्पपथ पर आगे बढ़ रही है।

इसी तरह दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में करोड़ों की राशि क्षेत्र में सड़क का जाल बिछ रहा है। ग्राम कोटनी नगपुरा के मध्य उच्चस्तरीय पुल निर्माण ,ग्राम नगपुरा में शिक्षा हेतु महाविधालय की स्थापना, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, कानून व्यवस्था के लिए ग्राम नगपुरा में पुलिस चौकी की स्थापना और एक सामाजिक भवन, ग्राम रसमडा में आई टी आई की घोषणा सहित अन्य विकास कार्य हुए हैं।

संविदा कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ सरकार को दी बड़ी चेतावनी, भूपेश बघेल की मुश्किल बढ़ी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने अपनी 1 सूत्रीय मांग नियमितीकरण को लेकर नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद संविदा कर्मचारियों ने आक्रोश रैली निकाली। लेकिन पुलिस ने लगभग 300 मीटर के बाद प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। प्रदर्शनरत कर्मचारियों ने सरकार के साल 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की मांग की।

कर्मचारियों ने निकाली रथ यात्रा-छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ की मांग पूरी नहीं होती है, तो 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में संविदा कर्मचारियों के साथ ही उनका पूरा परिवार दूसरी पार्टी को वोट देंगे।

सूरज सिंह ठाकुर, प्रांतीय प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी ने कहा 16 मई से सभी जिला मुख्यालय में रथ यात्रा का आयोजन करके अपनी मांग के संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश भर के लगभग 45 हजार संविदा कर्मचारी 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे।

दूसरी पार्टी को वोट देने की चेतावनी-प्रदर्शनकारियों ने छत्तीसगढ़ सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए चुनाव में इसका नतीजा भुगतने की चेतावनी दी। सूरज सिंह ठाकुर ने कहा कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाया गया लेकिन पिछले साढ़े 4 सालों से कांग्रेस सरकार ने नियमितीकरण को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की है। जिसके कारण संविदा कर्मचारियों में आक्रोश और नाराजगी है। कांग्रेस सरकार संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं करती है, तो 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी और उनका परिवार दूसरी पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर होंगे।

3 जुलाई से नाराज कर्मचारियों की हड़ताल-3 जुलाई से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। जिसका सीधा असर सरकार के कामकाज पर पड़ेगा। प्रदेश के लगभग 54 विभागों में 45 हजार संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनके हड़ताल पर चले जाने से सभी विभागों में कामकाज प्रभावित होने के साथ ही ठप भी हो सकते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि भूपेश सरकार नाराज कर्मचारियों को अपने पाले में लाने क्या करती है।

आज जिस शिक्षा नीति की चर्चा चल रही है, उसमें हम 15 साल पीछे हैं: कुलपति शुक्ला

रायपुर। महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय और विप्र कला एवं शिक्षण महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित नई शिक्षा नीति पर 7 दिवसीय कार्यशाला विगत दिवस समापन हुआ। विषय विशेषज्ञों ने काफी महत्वपूर्ण ढंग से अपनी बातें रखीं। कुलपति शुक्ला ने कहा कि आज जिस शिक्षा नीति की चर्चा चल रही है,उसमें हम 15 साल पीछे है,इसलिए हमें नई व्यवस्था से जुडना होगा। विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि आधुनिक शिक्षा पद्धति को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। शिक्षा प्रसार समिति के अध्यक्ष अजय तिवारी ने कहा की कार्यशाला में विद्वानों के व्याख्यान से काफी बिंदु सामने आए हैं जो भावी शिक्षकों के ज्ञान के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे

कार्यशाला के समापन अवसर के मुख्य अतिथि विधायक ग्रामीण सत्यनारायणशर्मा थे,विशिष्ट अतिथि डॉ सच्चिदानंद शुक्ला,कुलपति पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, श्री ज्ञानेश शर्मा ,अध्यक्ष राज्य योग आयोग, श्री अजय तिवारी ,अध्यक्ष शिक्षा प्रचारक समिति,श्री सुरेश शुक्ला समाजसेवी एवं डॉ देवाशीष मुखर्जी प्राचार्य महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय के साथ विप्र महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य डॉ विवेक मिश्रा गुरुकुल महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संध्या गुप्ता अग्रसेन महाविद्यालय के प्राचार्य आर राजपूत प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संगीता घई सहित विद्वतजन की कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति रही। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ सच्चिदानंद शुक्ला ने कहा कि हमें अपने कल्चर पर गर्व होना चाहिए इसी व्यवस्था में शिक्षार्थियों को शिक्षित करें नई शिक्षा नीति में मुख्य दो बातें खास तौर पर रखी गई है इसमें भारतीय संस्कृति और विश्व में शिक्षा की वर्तमान स्थिति के प्रमुख बिंदु है उन्होंने कहा आज जिस शिक्षा नीति की चर्चा चल रही है।

रायपुर। बोर्ड परीक्षाओं में विद्यालय के उत्कृष्ट रिजल्ट (10 वी में 99 फीसदी व 12वी में 100 फीसदी हेतु प्राचार्य के रूप में जिले स्तर पर विधायक कुलदीप जुनेजा, विधायक एवं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, मान. कलेक्टर एस एन भूरे सर तथा आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी आर एल ठाकुर सर द्वारा सम्मानित किया गया।

भाजपा और कांग्रेस जिताऊ प्रत्याशी की खोज में करा रही सर्वे

■ **कैंडिडेट का सिलेक्शन जिताएगा इलेक्शन**

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिसात बिछ रही है। सियासी दल चुनावी दंगल के लिए अपनी अच्छी सेना उतारना चाहते हैं। लिहाजा छत्तीसगढ़ में हर विधानसभा सीट के लिए सक्षम कैंडिडेट की तलाश चल रही है। खास बात यह है कि इस पूरी कवायद के लिए बाकायदा सर्वे का सहारा लिया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में चुनाव करीब है। लिहाजा सभी दल बेहतर उम्मीदवार की तलाश में जुटे हैं। भाजपा कांग्रेस सर्वे भी करा रहे हैं। इस सर्वे में उम्मीदवार के कामकाज की लोकप्रियता, सत्ता संगठन से संबंध सहित तमाम बातों का ध्यान रखा जा रहा है। दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर सर्वे करा रहे हैं। इस सर्वे के मापदंड भी अलग-अलग हैं, लेकिन इसमें कोई भी कुछ भी खुलकर बोलना नहीं चाहता। सभी का कहना है कि चुनाव के दौरान जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दी जाएगी।

सर्वे के आधार पर बांटा जाएगा टिकट- छत्तीसगढ़ में उम्मीदवार की तलाश में सर्वे का यह पहला मौका नहीं है। छत्तीसगढ़ में सर्वे की परंपरा रही है। दोनों ही पार्टियां सर्वे कराती हैं, हालांकि सर्वे की बात को स्वीकारती नहीं हैं। समय समय पर यह बातें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाती है।

कांग्रेस में सर्वे के आधार पर टिकट वितरण कितना मुश्किल

सर्वे की टिकट वितरण में अहम भूमिका होती है। वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे कहते हैं, साल 2013 विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने एक सर्वे कराया था। वह सर्वे के आधार पर टिकट बांटना चाह रहे थे। बस्तर में एक युवा शामू कश्यप को टिकट दी थी। बाद में विरोध हुआ तो राहुल गांधी भी अपनी सोच पर कायम नहीं रह पाए। कांग्रेस में एक तरह का लोकतंत्र है। ऐसे में क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन भाजपा में यह जरूर है कि सर्वे के आधार पर नए चेहरों का चयन हो सकता है।

13 सीटों वाली भाजपा के लिए सर्वे रिपोर्ट होगी काफी महत्वपूर्ण

अनिरुद्ध दुबे ने बताया कि सबसे ज्यादा सर्वे की जरूरत भाजपा को है, क्योंकि वह 2018 के चुनाव में अपना जनाधार खोकर 15 सीटों पर सिमट गई। अब 13 विधायक ही भाजपा के बचे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुत ज्यादा युवा और नए चेहरों को मौका दे सकती है। इसके लिए सर्वे रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी। सर्वे अभी हो रहा है और बाद में भी कुछ सर्वे होंगे उसके बाद चयन होगा कि किसे टिकट दी जाए और किसे नहीं।

टिकट कटेगी तो किस दल को ज्यादा नुकसान

कांग्रेस के पास वर्तमान में 71 विधायक हैं। सिटिंग विधायकों की रिपोर्ट और उसके आधार पर उनका टिकट काटना कांग्रेस के लिए एक टेढ़ी खीर हो सकती है, क्योंकि इन 71 विधायकों में से किसी की रिपोर्ट अच्छी तो किसी की खराब रिपोर्ट भी होगी।

90 विधानसभा में दलीय स्थिति

छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। 71 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। 14 सीटें भाजपा के पास थी, लेकिन भिलाई वैशाली के भाजपा विधायक विद्यारतन भसीन के निधन के बाद अब महज 13 सीटें रह गई है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के पास तीन और बहुजन समाजवादी पार्टी के पास 2 सीटें हैं। वर्तमान में 1 सीट खाली है।

क्या मरकाम और सैलजा में खिंचेगी तलवार ?

कहा जा रहा है कि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के आदेश को रद्द कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल उठाया जा रहा है कि प्रभारी महासचिव को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के कामकाज में दखल देने का

अधिकार है या नहीं ? सैलजा के फरमान के बाद अब तक मोहन मरकाम ने प्रदेश कांग्रेस के महामंत्रियों के काम का नए सिरे से बंटवारे वाले आदेश को निरस्त नहीं किया है। मरकाम ने सैलजा के पत्र की समीक्षा की बात कर कई संदेश दे दिए हैं। मरकाम के रुख को देखकर लोग अंदाज लगा रहे हैं कि उन्हें दिल्ली से किसी का आशीर्वाद मिला हुआ है। अध्यक्ष के तौर पर मरकाम का कार्यकाल पूरा हो चुका है, फिर भी वे पद में बने हैं। कुछ महीने पहले मरकाम की जगह सांसद दीपक बैज को अध्यक्ष बनाए जाने की हवा चली थी। हवा किधर गई पता नहीं चला। प्रदेश अध्यक्ष के लिए मरकाम का चयन राहुल गाँधी ने किया था। देखते हैं मरकाम झुकते हैं या सैलजा कोई रास्ता निकालती हैं। वैसे तो प्रदेश प्रभारी की भूमिका को रेफरी की तरह मानी जाती है। खबर है कि महामंत्री प्रशासन और संगठन का काम देख रहे रवि घोष को बस्तर भेजने और अमरजीत चावला को युवक कांग्रेस और

रवि भोई

एनएसयूआई की जिम्मेदारी देकर राजधानी में बैठाने से प्रदेश संगठन में बवाल मचा है। विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले सत्तारूढ़ दल में झगड़े से विपक्ष को वार का मौका मिल गया है।

भाजपा अध्यक्ष के नए-नए प्रयोग

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पार्टी को गति देने और कामकाज में निखार लाने के

लिए नए-नए प्रयोग शुरू कर दिए हैं। पार्टी की नीति तय करने लिए अनुसंधान का काम अब नेताओं की जगह बुद्धिजीवी करेंगे, वहीं अध्यक्ष जी के कार्यक्रम तय करने और दौरे के लिए भी अलग विभाग बना दिया गया। अध्यक्ष जी के नए-नए प्रयोग पर पार्टी के भीतर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सबसे ज्यादा चर्चा नीति अनुसंधान टीम को लेकर है। खबर है कि नीति अनुसंधान टीम में अब तक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडे, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद रामविचार नेताम थे। अध्यक्ष जी ने नेताओं की जगह नीति अनुसंधान का काम पार्टी प्रवक्ता और पार्टी से जुड़े बुद्धिजीवियों को सौंपा है। पुरानी टीम में प्रेमप्रकाश पांडे नीति अनुसंधान टीम के संयोजक हुआ करते थे। अब हिंदी ग्रन्थ अकादमी के पूर्व संचालक शशांक शर्मा को इस टीम का संयोजक बनाया गया है। इस टीम की लिस्ट में नाम का उलट-पुलट सुर्ख़ियों में हैं। कहते हैं इस टीम की पहली सूची में भाजपा के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी का नाम पांचवें नंबर पर था। कुछ घंटों बाद नई सूची जारी हुई, जिसमें अमित चिमनानी का नाम चौथे नंबर पर और उज्जवल दीपक का नाम चौथे से छठवें नंबर पर आ गया। नाम में ऊपर-नीचे का खेला लोगों के जिज्ञासा का कारण बन गया है।

सर्व आदिवासी समाज पार्टी बनाने की दिशा में

कहते हैं सर्व आदिवासी समाज 2023 के चुनाव के पहले राजनीतिक पार्टी बनाकर मैदान में जोर आजमाईश की कोशिश में लगी है। खबर आ रही है कि सर्व आदिवासी समाज हमर राज नाम से नई पार्टी पंजीकृत करवा कर आदिवासी इलाकों में अपना उम्मीदवार खड़े करेगी। माना जा रहा है कि सर्व आदिवासी समाज की तरफ से नई पार्टी बनाने की प्रक्रिया जारी है और चुनाव आयोग तक मामला पहुंच भी गया है। कहा जा रहा है कि सर्व आदिवासी समाज से जुड़े कुछ लोगों को कांग्रेस अपने पाले में करने की कोशिश में जुटी है, अब देखते हैं कांग्रेस को कितनी सफलता मिलती है। पहले ही प्रयास में भानुप्रतापपुर उपचुनाव में तीसरे स्थान पर आने से सर्व आदिवासी समाज के हौसले तो बुलंद हैं ही। आदिवासी समाज की तरफ कांग्रेस ही नहीं, भाजपा भी देख रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए आदिवासी विधायकों की अहम भूमिका रहती है।

निरंजन दास का क्या होगा?

रिटायर्ड आईएएस निरंजन दास को ईडी गिरफ्तार करेगी या नहीं ? इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। निरंजन दास शराब घोटाले में ईडी के निशाने पर हैं। जिला अदालत ने निरंजन दास की जमानत याचिका खारिज कर दी है , ऐसे में निरंजन दास को ईडी कभी भी अपने कब्जे में ले सकती है। निरंजन दास लंबे समय तक आबकारी आयुक्त थे। कहा जा रहा है कि निरंजन दास के कार्यकाल में ही राज्य में आबकारी घोटाला हुआ। डिप्टी कलेक्टर से आईएएस बने निरंजन दास को सरकार ने रिटायरमेंट के बाद संविदा नियुक्ति दी थी और वही विभाग सौंपे थे, जो विभाग उनके पास पहले से थे , लेकिन ईडी के फेर में फंसने के बाद सरकार ने उनसे सारे विभाग वापस ले लिए और करीब आधा दर्जन अफसरों में बांट दिए।

सेवावृद्धि के लिए आईपीएस का दिल्ली में डेरा

कहते हैं राज्य के एक आईपीएस अपनी सेवावृद्धि के लिए पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। ये अफसर जल्दी ही सेवानिवृत होने वाले हैं। कह जा रहा है ये

अफसर भारत सरकार में कई पदों पर प्रतिनियुक्ति पर रहें। इस कारण केंद्र सरकार के अधिकारियों से इनके संबंध अच्छे हैं। आईपीएस अफसरों को भारत सरकार ही सेवावृद्धि देती है। भले इसके लिए राज्य सरकार से केंद्र सरकार को प्रस्ताव जाता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राज में अभी तक किसी आईएएस या आईपीएस को सेवावृद्धि नहीं मिली है।

क्या अब ईडी की कार्रवाई तेज होगी ?

कयास लगाया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद ईडी की कार्रवाई तेज होगी। कहते हैं पिछली बार अमित शाह के राज्य के दौरे से जाने के बाद ईडी की कार्रवाई तेज हुई थी। वैसे भी 22 जून को दुर्ग की सभा में अमित शाह ने भूपेश सरकार पर तीखे हमले किए। हवा उड़ी है कि राज्य में जून के आखिरी या जुलाई के पहले हफ्ते में ईडी धमाका कर सकती है। ईडी अब तक कोयला, शराब और कृषि उपकरणों की सप्लाई करने वालों को अपने निशाने पर ले चुकी है। पिछले दिनों आयकर विभाग ने सोलर पैनल सप्लाई करने वालों पर छापा डाला था। सोलर पैनल सप्लाई में बड़ा गड़बड़ झाला होने पर ईडी को जांच सौंपने की खबर है।

वैशाली नगर सीट में नहीं होगा उपचुनाव

भाजपा विधायक विद्यारतन भसीन से रिक्त वैशाली नगर विधानसभा सीट के लिए अब उपचुनाव की कोई संभावना नहीं है। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए संभवत: अक्टूबर में अधिसूचना जारी हो जाएगी। इस कारण उपचुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विद्यारतन भसीन का दो दिन पहले ही निधन हुआ है। विधानसभा के रिक्त सीट पर छह माह के भीतर चुनाव कराने होते हैं। विधानसभा सचिवालय एक-दो दिन के भीतर चुनाव आयोग को वैशाली नगर विधानसभा सीट रिक्त होने की सूचना भेज देगा। इस अवधि के बाद छह माह के भीतर राज्य में विधानसभा चुनाव ही हो जाएगा।

जज पर गिरी गाज

कहते हैं हाईकोर्ट ने एक जज को राज्य के शीर्ष पद से जिला स्तर के पद पर भेज दिया। छत्तीसगढ़ में यह दूसरा मर्तबा है जब हाईकोर्ट ने एक जज को राज्य के शीर्ष पद से जिला स्तर के पद पर भेजा है। कहा जा रहा है इस जज के कुछ रिश्तेदार गड़बड़ी के मामलों में जेल में हैं। इन मामलों की आंच जज पर भी आई थी।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार और पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक हैं।)

उग्रवादी और चर्च के सहारे है कांग्रेस: गिरीराज

जगदलपुर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि यह छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार नहीं, बल्कि डपोरशंख की सरकार है, उग्रवादियों और चर्च के सहारे यह लोग चुनाव लड़ते हैं। ष्ट्र धर्मांतरण का केंद्र बिंदु बन गया है। इधर, आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने चैलेंज करते हुए कहा कि, भाजपा यदि भूपेश सरकार में एक भी धर्मांतरण होना बता दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा कि, ये लोग सिर्फ दमन करते हैं।

दरअसल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ओडिशा दौरे पर थे। वे वहां से सीधे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर आए। यहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। इस दौरान गिरिराज सिंह ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर

निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, बस्तर धर्मांतरण का हेड ऑफिस बन गया है। डपोरशंख सरकार के लोग कहते हैं कि राम मेरा भांजा है, कौशल्या बहन है।

गिरिराज सिंह ने उदाहरण देते हुए कहा कि कंस भी कहता था कि श्रीकृष्ण मेरा भांजा है। अब आप लोग यह समझ जाइए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। गिरिराज सिंह का कहना है कि, जिस कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक प्रभु श्रीराम को नहीं स्वीकारा, राम सेतु को नहीं स्वीकार, अब वे उनके नाम पर रामलीला कर रहे हैं। ये लोग डरे हुए हैं।

मंत्री लखमा ने किया चैलेंज

वहीं, आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि, भाजपा का सिर्फ एक ही काम रहा है फूट डालो और राज करो। झूठ बोलो और कुर्सी पर बैठो। वर्तमान में यह यही काम कर रही है। इससे पहले भी मैंने विधानसभा में चैलेंज किया था कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में पूरे छत्तीसगढ़ और बस्तर में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ है। ये लोग साबित भी नहीं कर पा रहे हैं। मैंने पहले भी चैलेंज किया था और अब भी चैलेंज कर रहा हूं ,एक भी धर्मांतरण हुआ बता दो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन यह लोग मेरे चैलेंज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज बोले- गोडसे भारत के सपूत-उनका जन्म भारत में हुआ, औरंगजेब और बाबर की तरह नहीं थे गिरिराज सिंह ने एक जगदलपुर में सभा को संबोधित किया था।

गिरिराज सिंह ने एक जगदलपुर में सभा को संबोधित किया था। 15 दिन पहले छत्तीसगढ़ पहुंचे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह ने कहा था कि नाथूराम गोडसे भारत के सपूत थे। सिंह ने कहा-गोडसे गांधी जी के हत्यारे हैं तो वे भारत के सपूत भी हैं। उनका जन्म भारत में ही हुआ था। औरंगजेब और बाबर की तरह नहीं थे। जिसको बाबर के बच्चे कहलाने में खुशी महसूस होती है, वे भारत माता के सही सपूत नहीं हो सकते।

अपना वजूद बचाएं मरकाम : कश्यप

रायपुर। प्रदेश भाजपा महामंत्री व छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम को सलाह दी है कि वह पहले अपनी कुर्सी और अपना वजूद बचाएं, उसके बाद बयानबाजी करके अपनी राजनीति चमकाएं तो उनके लिए बेहतर होगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि इंदिरा प्रियदर्शिनी सहकारी बैंक घोटाले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मरकाम बेजा टिप्पणी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि रमन सरकार के मंत्रियों की संपत्ति को कुर्क कर बैंक घोटाले की भरपाई की जाए तो यह मांग उन्हें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से करना चाहिए कि भूपेश बघेल के राज में जितने भी घोटाले हुए हैं, उनकी भरपाई भूपेश बघेल और उनके भ्रष्टाचारी मंत्रियों की संपत्ति कुर्क करके करना चाहिए। उन्हें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करनी चाहिए कि दो हजार करोड़ के आर्गेनाइज्ड सिंडीकेट नेटवर्क द्वारा किए गए शराब घोटाले की रकम की भरपाई भूपेश सिंडिकेट की संपत्ति कुर्क करके छत्तीसगढ़ शासन के खजाने में जमा करनी चाहिए।

रमन सिंह ने केन्द्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां

राजनांदगांव। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घर-घर शराब पहुंच रही है सारे वादे पूरे नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार जनता के आम मुद्दों को लेकर उनके बीच जाएगी।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव के दौरे पर थे। इस दौरान शहर के एक निजी होटल में उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विभिन्न योजनाओं के संबंध में चर्चा करने के साथ ही प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं इस दौरान सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे।पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से चर्चा की उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर उपलब्धियां बताई। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूर्ण नहीं करने का आरोप लगाया। रमन सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश सरकार के घोषणा पत्र में किए गए वादों को लेकर जनता के बीच जायेगी। कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं किया है,सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है जनता के मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा मैदान में उतरेगी।

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घर-घर शराब पहुंच रही है सारे वादे पूरे नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार जनता के आम मुद्दों को लेकर उनके बीच जाएगी और कांग्रेस द्वारा किए गए वादाखिलाफी को लेकर भी लोगों के बीच जाकर चुनाव मैदान में उतरेगी।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

नक्सली भाजपा नेताओं की हत्या कर रहे: चंदेल

रायपुर। बस्तर में भाजपा नेताओं को नक्सली मार रहे हैं। बीते 6 महीनों में 6 भाजपा नेताओं की हत्या हो चुकी है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। चंदेल ने कहा है कि भाजपा के नेताओं को टारगेट

कर उनकी हत्या की जा रही है। हमारे नेताओं को नक्सली धमका रहे हैं, इस्तीफा देने कह रहे हैं। जो क्षेत्रों में सक्रिय हैं उनकी हत्या हो रही है।शनिवार को इस पर मीडिया से बातचीत में चंदेल ने कहा- पूरे बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों का, माओवादियों का राज है। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में आई है, तब से नक्सल घटनाएं भी बढ़ी हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग हुई, प्रजातंत्र में लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले साढे 4 साल से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बस्तर में पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। किसी कार्यक्रम में जाने से भाजपा नेताओं को नक्सली रोक रहे हैं। धमकी भरे पत्र भेजे जा रहे हैं, सूचनाएं दी जा रही हैं कि आप कोई कार्यक्रम में ना जाएं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने को कहा जा रहा है। यह लोकतंत्र में कहीं उचित नहीं है।बुधवार 21 जून को नक्सलियों ने बीजापुर में भाजपा नेता की हत्या की थी। बीजापुर इल्मीडी गांव में नक्सलियों ने भाजपा नेता काका अर्जुन की हत्या कर दी थी।

हिन्दू हित का दिखावा करती है कांग्रेस: आलोक कुमार

रायपुर। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार हिंदुओं के हित में काम कर रही है, ये दिखाने की कोशिश करती है. लेकिन जब हिंदू और मुस्लिम दोनों

में से किसी एक को चुनने की बात आती है, तो वह झिझक जाती है. आलोक कुमार ने कहा कि जो पार्टी हिंदुत्व का सोचती हैं, हम उसका समर्थन करते हैं. कांग्रेस निर्णय करेगी कि वो किधर जाना चाहती है. धर्मांतरण को लेकर उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार के समय में धर्मांतरण हो, गलत है. लेकिन छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है.चुनाव की वजह से धर्मांतरण के मुद्दे को उठाए जाने के सीएम भूपेश बघेल के आरोप को आलोक कुमार ने खारिज करते हुए कहा कि अभी चुनाव का समय है, हम जहां भी बैठक करेंगे, वहां पर चुनाव से जोड़ा जाएगा.वहीं छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण के आयोजन का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार कोई भी हो, रामायण महोत्सव करेगी तो हमे आंनद होगा. जनता भी समझती है कि हृदय से हो रहा है, या राजनीति के लिए किया जा रहा है.विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक का जिक्र करते हुए आलोक कुमार ने कहा कि बैठक में लव जिहाद, धर्मांतरण, महिलाओं के प्रति अन्याय रोकने पर विचार किया जा रहा है. यूनिफार्म सिविल कॉर्ड लाने सरकार कदम बढ़ा रही है, हम इसका स्वागत करते हैं.

टारगेट किलिंग भाजपा की संस्कृति: धनंजय

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की लाशों पर राजनीति करने की आदत है। 15 साल के रमन सरकार के दौरान नक्सली गतिविधियां बढ़ी थी, आज

नक्सली गतिविधियों में 80 प्रतिशत की कमी आई है। नक्सलियों के द्वारा भाजपा के कार्यकर्ता की गई हत्या बहुत दुखद है। भाजपा कार्यकर्ता की हत्या को टारगेट किलिंग बताकर भाजपा ओछी राजनीति कर रही है। टारगेट किलिंग भाजपा नेताओं की संस्कृति है। आजादी के बाद नाथूराम गोडसे ने टारगेट कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की। रमन सरकार के दौरान परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा हटाकर झीरम घाटी में षड़यंत्रपूर्वक कांग्रेस नेताओं की टारगेट कर हत्या की गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जिस दिन हत्या हुई उसी दिन कुछ लोग हत्या की खबर सुनने के बाद नागपुर में मिठाई वितरित कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे, देश में कांग्रेस के नेता ही टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी टारगेट किलिंग कर हत्या की गई थी और इन सब का मकसद सिर्फ कांग्रेस के मजबूत नेतृत्वकर्ताओं को खत्म कर राजनीति को कमजोर करना था। कांग्रेस नेताओं की हत्या कर गांधी जी की अहिंसा की विचारधारा को खत्म करने का प्रयास किया गया।

भाजपा की डूबती नैय्या बचाने का एजेंडा : शुक्ला

रायपुर। विश्व हिन्दू परिषद की बैठक में धर्मांतरण को लेकर की गयी चिंता को कांग्रेस ने भाजपा की डूबती नैय्या को बचाने का एजेंडा बताया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जबरन धर्मांतरण को सुप्रीम

कोर्ट ने देश के लिये बड़ी समस्या बताया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद केन्द्र में बैठी मोदी सरकार का यह कर्तव्य बन जाता है कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ वह पूरे देश में एक कानून बनाये। भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण को लेकर देश भर में अफवाह फैलाने और राजनीति करने का काम करती है। लेकिन जब इस मामले में ठोस पहल करने या कानून बनाने की बात आती है तब भाजपा की नीयत में खोट साफ नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण और सांप्रदायिकता पर सिर्फ राजनीति करना चाहती है। वह नही चाहती इस समस्या का कोई ठोस निदान हो। सुप्रीम कोर्ट धर्मांतरण पर चिंतित है वह देश में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनने की वकालत कर रही है। ऐसे में मोदी सरकार इस मामले पहल कर शीघ्र कानून बनाना चाहिये। लेकिन जब यह समस्या पूरे देश की है तब एक राष्ट्र एक कानून के सिद्धांत का पालन धर्मांतरण में भी होना चाहिये। शुक्ला ने कहा कि विहिप अपने बैठक में धर्मांतरण को लेकर चिंता व्यक्त करती है लेकिन अपने ही सहयोगी केन्द्र सरकार को कानून बनाने के लिये उसने कोई प्रस्ताव पारित नही किया।

रायपुर स्मार्ट सिटी कराएगा मोर रायपुर दर्शन

रायपुर। स्मार्ट सिटी मिशन की 8 वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित मोर रायपुर दर्शन में शामिल होकर नागरिक रायपुर स्मार्ट सिटी लि. की परियोजनाओं से अवगत होंगे। यह विशेष आयोजन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय,

भारत सरकार के मार्गदर्शन में रायपुर स्मार्ट सिटी लि. द्वारा 26 जून को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न संगठनों के साथ ही सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन, युवा व शहरवासी सम्मिलित होंगे।

मोर रायपुर दर्शन की शुरुआत सुबह 10 बजे सदर बाजार सिटी कोतवाली परिसर में स्थित रायपुर स्मार्ट सिटी लि. के मुख्यालय से होगी, जहां छठवीं मंजिल के व्यू प्वाइंट से आम नागरिक शहर के विहंगम दृश्य का अवलोकन करेंगे। भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत जे.आर. दानी स्कूल, हेरिटेज वॉक रूट, कंकाली तालाब, ऐतिहासिक आनंद समाज वाचनालय, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना अंतर्गत संचालित आर.डी. तिवारी स्कूल के नव निर्मित भवन, प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे युवाओं के लिए बने नालंदा परिसर, शहर के यातायात प्रबंधन व सर्विलेंस की अतिआधुनिक प्रणाली दक्ष कमांड सेंटर, नंदकुमार पटेल चौक के समीप ऑक्सीजोन, घड़ी चौक, छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा स्थल एवं मल्टीलेवल पार्किंग आदि का अवलोकन नागरिक करेंगे।

विहिप ने समान नागरिक संहिता की मांग रखी

- बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा

रायपुर। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक में विहिप ने समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए कहा कि यह शीघ्र लागू होना चाहिए। देश में सभी धर्मों के लोगों को इसका पालन करना चाहिए। पत्नी, बच्चों के अधिकार, वैवाहिक अधिकार और विवाह के लिए आयु संबंधी अधिकार किसी अन्य धर्म के लिए अलग नहीं हो सकते हैं। राजधानी के कमल विहार स्थित माहेश्वरी भवन में आयोजित बैठक में विहिप के

केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि विहिप समान नागरिक संहिता की मांग करता है।

एक धर्म विशेष के द्वारा संविधान के नियमों का लगातार उल्लंघन किया जाता है, जिसका नुकसान महिलाओं और बच्चों को उठाना पड़ रहा है। यही कारण है कि अब राष्ट्रीय विधि आयोग ने भी आम लोगों से इस संदर्भ में सुझाव आमंत्रित किया है। 14 जुलाई तक आम लोग सुझाव दे सकते हैं। विहिप ने साफ तौर पर एलान किया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-44 का पालन सभी को करना चाहिए।

विहिप की बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जा रही है उसमें मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त कराना, लव-जिहाद के खिलाफ आंदोलन, गो-हत्या रोकने कड़े कानून और मतांतरण रोकना है। इन मुददें पर विभिन्न राज्यों के पदाधिकारी अपनी बात रखेंगे। केंद्रीय समिति की बैठक में देशभर के 41 प्रांतों के लगभग 200 पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं।

आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या व तानाशाही ही कांग्रेस का असली चरित्र : उपासने

रायपुर। वरिष्ठ भाजपा नेता और लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अपनी सत्ता बचाने के लिये न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर त्यागपत्र न देकर देश में आपातकाल लगा हजारों विपक्षी नेताओं को रातों-रात 21 माह तक के लिए जेल की सीखचों में डालना, समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा उनकी स्वतंत्रता छिन लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस की तानाशाही का जीवन्त प्रमाण है। उपासने ने कहा कि यह कांग्रेस के इतिहास व देश के लोकतंत्र पर काला धब्बा व काला इतिहास है। छत्तीसगढ़ सरकार आज भी कांग्रेस के तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या व न्यायालय के आदेश को न मानने की हठधर्मिता की राजनीति कर रही है, यही

कारण है कि आपातकाल में जिन राष्ट्र भक्तों को कांग्रेस की राज्य सरकार ने 21माह तक बिना किसी वैधानिक आदेश के जेल की सीखचों में डाल उनके परिवारों को नेस्तनाबूत कर दिया उन्हें भाजपा रमन सरकार ने सम्माननिधि दे सम्मानित किया जिसे भूपेश सरकार ने सत्ता में आते ही दुर्भावनापूर्ण व वंशवाद को खुश करने बंद कर दिया, शासन के इस आदेश को सेनानियों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी जिस पर सिंगल व डबल बेंचों ने सरकार के आदेश को निरस्त कर तत्काल सम्माननिधि देने के आदेश सरकार को दिये पर आदेश का पालन न कर अपनी दुर्भावना के चलते सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर पेशियां ले लेकर सेनानियों को अपने लोकतान्त्रिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.